



आईपीएस बंदी नारायण मीणा बने बस्तर के नए आईजी

रायपुर, 25 जून। आईपीएस बंदी नारायण मीणा बस्तर के नए पुलिस महानिरीक्षक होंगे। वे सुंदरराज पी की जगह लेंगे। बंदी मीणा के कार्यभार ग्रहण करने पर सुंदरराज बस्तर से



रिलीव होकर सेंट्रल डेप्युटेशन के लिए जाएंगे। सुंदरराज रिकार्ड सात साल बस्तर में लगातार डीआईजी और आईजी रहे। उससे पहले सात साल एएसपी और एएसपी रहे। याने कुल 14 साल वे बस्तर में रहे। बंदी नारायण मीणा 2004 बैच के आईजी हैं। उनके नाम सबसे अधिक नौ जिलों के एएसपी रहने का रिकार्ड दर्ज है। बंदी मीणा रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग पुलिस रेंज के आईजी रह चुके हैं। वे दुर्ग में दो बार आईजी रहे। पुलिस अधीक्षक के तौर पर वे सरगुजा से लेकर बस्तर तक के कई जिलों में काम कर चुके हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव इन टॉप के जिले में भी बतौर कप्तान अपनी भूमिका निभा चुके हैं।

घर में फटा एसी, एक की मौत, एक घायल

रायगढ़, 25 जून। रायगढ़ से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहाँ गुरुवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आईटीआई कॉलोनी (अंबेडकर नगर) में सुबह करीब 3:30 बजे एक मकान में एयर कंडीशनर ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया इस भीषण हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास की दीवारें हिल गईं। घर के अंदर रखा सामान और परिसर में खड़ी दो मोटरसाइकिलें भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गईं।

कोलकाता हादसे पर पीएम ने जताया दुःख

नई दिल्ली, 25 जून। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुःख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, पीएम मोदी ने मृतक के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही, घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बुधवार को कोलकाता में हुई दुर्घटना दुःखद है। इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। साइबर ठगों के ठिकानों सीबीआई का छाप

नई दिल्ली, 25 जून। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर देश और दुनिया भर के मासूम लोगों को डराकर करोड़ों रुपये ऐंठने वाले इंटरनेशनल साइबर ठगों के खिलाफ सीबीआई ने 'ऑपरेशन चक्र-VI' छेड़ दिया है। डिजिटल अरेस्ट गिरोह पर फिजा का कसते हुए देश के 16 राज्यों में एक साथ 80 से ज्यादा ठिकानों पर गुरुवार सुबह छापेमारी की गई। सीबीआई ने गिरोह के दो बदमाशों को अरेस्ट किया है।

वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का जलजला, 10 हजार से ज्यादा मौत

काराकस, 25 जून। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम आए दो बड़े भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है। 4.5 सेकंड के अंदर आए 7.1 तीव्रता और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप ने वेनेजुएला में हर जगह सिर्फ तबाही और बरबादी छोड़ा है। वेनेजुएला में भूकंप से सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गईं। वहीं 10 हजार से अधिक लोगों के मरने की संभावना है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिग ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। हालांकि अभी तक सरकार ने किसी मौत के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं। यह पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। इससे पहले 1900 में 7.7 का तीव्रता का भूकंप आया था। राहत और बचाव अभियान जारी है। यूएस जियोलाॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था और इसका केंद्र



राजधानी काराकस से करीब 20 किमी दूर काराबोबो राज्य में था। इसके कुछ ही सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा और ज्यादा शक्तिशाली भूकंप आया। अमेरिकी

सैकड़ों इमारतें जमींदोज, एयरपोर्ट भी तबाह

जियोलाॉजिकल सर्वे यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलाॉजिकल सर्वे (यूसजीएस) ने भूकंप से वेनेजुएला में 10 हजार से ज्यादा मौतों की आंशका जताई है। यूसजीएस के मुताबिक भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की 44% और 1,00,000 से ज्यादा मौत की 30% आंशका है। अमेरिकी जियोलाॉजिकल सर्वे के मुताबिक, यह वेनेजुएला में पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। इससे पहले साल

1900 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। यूसजीएस ने चेतावनी दी है कि इस भूकंप में भारी जनहानि हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले भूकंपों ने पूरे दक्षिण अमेरिका को इलाके को हिलाकर रख दिया। भूकंप का असर वेनेजुएला से करीब 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन जैसे शहरों में दिखा। इन शहरों में भी इमारतों को खाली कराना पड़ा। बुधवार देर रात, कार्यवाहक राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिग ने कहा कि वह देश को संबोधित करने की तैयारी कर रही थीं।

राजधानी काराकस में सबसे ज्यादा असर-भूकंप का सबसे ज्यादा असर राजधानी काराकस में देखने को मिला है। राजधानी काराकस में कई इमारतें और घर गिर गए। काराकस एयरपोर्ट की छत का कुछ हिस्सा गिर गया।

लेक्चरर को बीईओ के पद का अतिरिक्त प्रभार देना कानून के विपरीत : हाईकोर्ट

बिलासपुर, 25 जून। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में साफ कहा है, शिक्षक का काम शिक्षकीय कार्य को अंजाम देना है, प्रशासनिक कामकाज संभालना नहीं। लेक्चरर को बीईओ के पद का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने को कानून के विपरीत माना है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े मामले में साफ कहा है, शिक्षकीय संवर्ग के कर्मचारियों को प्रशासनिक पदों का प्रभार नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा, शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, सिवाय उन विशेष परिस्थितियों के, जिनकी अनुमति बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत दी गई है।

इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने बलौदा के बीईओ का अतिरिक्त प्रभार, लेक्चरर को सौंपने संबंधी आदेश को नियमों और कानून के विपरीत मानते हुए निरस्त कर दिया। मामला बलौदा के प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी रवि कुमार गौतम द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिका में कहा है, वे एबीईओ के पद पर कार्यरत हैं और विभाग ने उन्हें प्रभारी बीईओ का दायित्व सौंपा था। इसके बावजूद 10 जून 2026 को जारी आदेश से पीएम श्री स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, बलौदा के प्रभारी प्राचार्य एवं व्याख्याता अनिल कुमार शर्मा को बीईओ का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, अनिल कुमार शर्मा मूलतः व्याख्याता हैं और शिक्षकीय संवर्ग से आते हैं।



हाईकोर्ट ने राजस्व मंडल का आवेदन किया खारिज

निरक्षर ग्रामीणों को देरी से दायर याचिका पर भी मिलेगा न्याय का अवसर

बिलासपुर, 25 जून। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने समय-सीमा और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि सुदूर वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, कम पढ़े-लिखे और आदिवासी वर्ग के लोग अपने मामलों में पूरी तरह वकीलों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे लोगों को केवल इस आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता कि उन्होंने समय पर अपील या पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं की। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सात ग्रामीणों की विलंब से दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने मामले को पुनर्विचार के लिए राजस्व मंडल

को वापस भेजते हुए सभी पक्षों को सुनकर गुण-दोष के आधार पर नया निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मामला मरियमपारा निवासी 68 वर्षीय कोदिया उरांव और अन्य ग्रामीणों से जुड़ा है। ग्रामीण लंबे समय से जिस भूमि पर मकान बनाकर रह रहे थे, वहां से बेदखली की कार्रवाई तहसीलदार द्वारा शुरू की गई थी। इसके खिलाफ ग्रामीणों ने सरगुजा संभाग आयुक्त न्यायालय में अपील दायर की थी। हालांकि 21 जुलाई 2025 को आयुक्त न्यायालय ने तहसीलदार के आदेश को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी थी। ग्रामीणों का कहना था कि वे दूरस्थ वनांचल क्षेत्र के निवासी और निरक्षर हैं, इसलिए उन्हें आयुक्त न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं मिल सकी। जनवरी 2026 में जब प्रशासन उनके मकानों को हटाने पहुंचा, तब उन्हें मामले की

जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल में पुनरीक्षण याचिका दायर की और देरी माफ करने का आवेदन भी प्रस्तुत किया। राजस्व मंडल ने 9 मार्च 2026 को आवेदन खारिज करते हुए कहा था कि ग्रामीणों ने अपने अधिवक्ता से मामले की जानकारी लेने का प्रयास नहीं किया, जो उनकी लापरवाही को दर्शाता है। इसी आदेश को चुनौती देते हुए ग्रामीण हाईकोर्ट पहुंचे थे। न्याय का उद्देश्य अधिकारों की रक्षा- हाईकोर्ट-सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि वे आदिवासी समाज के गरीब और निरक्षर लोग हैं तथा पूरी तरह अपने वकील पर निर्भर थे। जैसे ही उन्हें बेदखली की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी।

280 बोरी डीएपी खाद से भरी मेटाडोर जब्त

गरियाबंद, 25 जून। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में अवैध खाद परिवहन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 280 बोरा अवैध डीएपी खाद से भरे एक मेटाडोर को पकड़ा है। जब्त खाद की कीमत 3.50 लाख रुपए आंकी गई है। यह पूरा मामला देवभोग थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान अवैध डीएपी खाद से भरे मेटाडोर को पकड़ा। पुलिस ने मेटाडोर के अंदर से 280 खाद का बोरा जब्त किया, जिसकी

कीमत 3.50 लाख रुपए आंकी गई है। वाहन चालक ने बताया कि उसने 8 हजार के किराए पर उरमाल के एक लाइसेंस व्हायर की कहने पर यह अवैध परिवहन कर रहा था। खाद को ओडिसा सीनापाली से जांगड़ा ले जाया जा रहा था, जहां एक मक्का कारोबारी को दिया जाता। पुलिस ने जब्त 280 बोरा डीएपी खाद को आगे की कार्रवाई के लिए कृषि विभाग के सुपुर्द कर दिया है। दरअसल, इस बार युद्ध के चलते रासायनिक खाद का उत्पादन प्रभावित हुआ है, सरकारी सप्लाई भी घट गया है।

भाजपा बेशर्म पार्टी, बच्चों की किताब में भी करती है राजनीति: जयवर्धन सिंह

रायपुर, 25 जून। मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने एनसीडीआरटी की किताब में आपातकाल को शामिल करने पर रोष जताते हुए भाजपा को बेशर्म पार्टी करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी राजनीति में बच्चों की किताबों को भी शामिल करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीति जरूर करती है, लेकिन कभी बच्चों के भविष्य को इसमें शामिल नहीं करती। भाजपा बच्चों के भविष्य पर भी राजनीति करने वाली पार्टी है। बिलासपुर में नीट घोटाले को लेकर कांग्रेस की ओर से देशभर में 'छात्रों की गुंज' कार्यक्रम के संबंध में होने वाली प्रेस वार्ता में शामिल होने रायपुर पहुंचे मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री रहे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि 'छात्रों की गुंज'



कार्यक्रम देशभर में आयोजित किया जाएगा। इसी केपेन के अधीन देशभर के 28 शहरों में प्रेस वार्ता रखी है। बिलासपुर में होने वाली प्रेस वार्ता में शामिल होऊंगा। उन्होंने कहा कि पहली बार देश के इतिहास में हमने देखा है कि सीबीएसई शिक्षा, जो कांग्रेसी ने दी थी, उसमें घोटाला हो रहा है। धर्मद प्रधान के कार्यक्रम में दो बार नीट पेपर लीक हुआ है। कांग्रेस ने देश को पहला आईआईटी, आईआईएम और एआईआईएमएस दिया था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने नीट घोटाला और सीबीएसई घोटाला दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि जब एनटीए का गठन किया गया था, तो संसदीय अधिकार क्यों नहीं दिया गया।

सत्ता के अहंकार में कुचली गई संविधान की आत्मा : साय

रायपुर, 25 जून। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संविधान हत्या दिवस पर कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने 25 जून 1975 को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का 'काला दिवस' करार दिया। साय ने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार पर आपातकाल थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा सत्ता के अहंकार में संविधान की आत्मा को कुचला गया। मीसा के तहत हजारों लोकतंत्र सेनानी और पत्रकार जेल भेजे

गए। उन्होंने कहा कि 25 जून लोकतंत्र का काला दिवस है। आइए, हम सब मिलकर इस दिन संविधान की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प लें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किए जाने के फैसले का स्वागत किया। 25 जून 1975 - भारतीय लोकतंत्र का वह काला दिवस, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के सत्ता के अहंकार ने संविधान की आत्मा को कुचलकर पूरे देश पर आपातकाल थोप दिया।

खरोरा में धर्मांतरण, दो पास्टर गिरफ्तार

ईसाई समाज ने थाने में जमकर किया विरोध

खरोरा, 25 जून। रायपुर ग्रामीण के खरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मांठ में धर्मांतरण से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। हिंदू देवों-



देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो पास्टर को गिरफ्तार किया है। वहीं इस गिरफ्तारी के विरोध में ईसाई समाज के लोग बड़ी संख्या में थाने पहुंचे और कार्रवाई की गलत आरोपों के

आधार पर की गई गिरफ्तारी बताते हुए विरोध जताया। मामला खरोरा थाना क्षेत्र का है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से और आरोपियों को आगे की पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया के लिए उन्हें विधानसभा थाना लाया गया है।

ग्रामीणों की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला-मामला तब सामने आया जब ग्राम मांठ निवासी हेमंत मरावी ने अरुण कुमार उड़के और राकेश कुमार उड़के के साथ खरोरा थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि रायपुर निवासी पास्टर सुशांत ज्ञानिक और उसका सहयोगी पीयूष पटेल पिछले कुछ समय से गांव के आदिवासी मोहल्ले में लगातार आ-जा रहे थे और ग्रामीणों से संपर्क कर उन्हें हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे।

नड़दा से साय की खाद-बीज उपलब्धता पर चर्चा

नई दिल्ली, 25 जून। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान जनस्वास्थ्य, चिकित्सा अधोसंरचना, औषधि एवं उर्वरक क्षेत्र सहित विभिन्न विभागीय और समसामयिक विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। विशेष रूप से दूरस्थ, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और अन्य चिकित्सा संस्थानों को मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर उपचार और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं अपने ही राज्य में उपलब्ध हों। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि और उर्वरक क्षेत्र से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि राज्य में किसानों को खाद और बीज की पर्याप्त एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।



सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े तथा खरीफ सीजन के दौरान आवश्यक कृषि आदानों की आपूर्ति सुचारु रूप से बनी रहे।

छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट एथलीट चयन प्रक्रिया: प्रतिभावान खिलाड़ियों के भविष्य से कोई खिलवाड़ न करें

कौन हैं जो प्रधानमंत्री की सोच पर लगा रहे सेंध?

आलेख .. जसवंत क्लॉडियस, वरिष्ठ स्वतंत्र खेल पत्रकार, टीवी कमेंटेटर, रायपुर, छ ग।

मई 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार की सत्ता संभाली है, तब से भारत के खेल परिदृश्य में बहुत से सकारात्मक बदलाव आये हैं। यह सब कुछ प्रधानमंत्री की स्वयं की सोच और भारत को खेल संसार में विश्व गुरु बनाने की इच्छाशक्ति का परिणाम है। कोई माने या ना माने यह सोच और चाहत सत्य भी हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में शरीर को स्वस्थ व चुस्त दुरुस्त रखने के लिए 2014 में भारत के सबसे पुराने व्यायाम, कसरत अर्थात योग को अपनाते का प्रस्ताव रखा। जिसे 14 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को योगसभ के आयोजन की जानकारी मिल रही है। इस प्रकार हम बड़े ही गर्व के साथ कह सकते हैं चूंकि आज संपूर्ण विश्व में योग की क्रियाओं को विदेशियों द्वारा अपनाया गया है और भारत सरकार ने योग को योगसभ के नाम से खेल का दर्जा दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत खेल का विश्व गुरु बन चुका है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाड़ियों को ओलंपिक व नान ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक पदक हासिल करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है अतः खेलों इंडिया मिशन के अंतर्गत

हमारे देश में ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र में उपलब्ध प्रतिभाओं को चयनित करके उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है, और इसी वजह से 18, 20, 21 तक के आयु वर्ग के उद्योगमान खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेशी खिलाड़ियों से मुकाबला करने के लिए उन्हें भारत सरकार के खेल मंत्रालय के खर्च से विदेश भेजा रहा है। इससे हार या जीत मायने नहीं रखती लेकिन परंतु खिलाड़ियों को न सिर्फ नई रणनीति, नई तकनीक की जानकारी हो रही है। बल्कि उन उभरते खिलाड़ियों को अपने आप पर, अपने प्रशिक्षण पर, अपनी मेहनत पर विश्वास खरा रहा है कि हम इसी तरह प्रयास करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को ना सिर्फ पूरा करेंगे बल्कि भारत का तिरंगा पूरी दुनिया में फहरा देंगे। दूसरी तरफ सुनने में आ रहा है कि खुद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने खिलाड़ियों के हित में बनाये गये कुछ अतिआवश्यक नियम का स्वयं ही पालन नहीं कर रहे हैं। एक कदम तब तक है जब माता-पिता, अभिभावक और स्वयं खिलाड़ी ओलंपिक के कोर थूप वाले खेल समूह में शामिल हो या ना हो, खेलने को शुरुवात करता है। तो वह खेल के माध्यम से उज्ज्वल व सुरक्षित भविष्य की उम्मीद रखता है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ में विभिन्न खेलों के ऐसे खिलाड़ी हैं जो आर्थिक रूप से अभावग्रस्त होते हुए भी अपनी पसंद के खेल को अपना रहे हैं। जब जुते, मोजे, शर्ट, पैंट, गैट, आदि खेल सामग्री खरीदने की बात आती है तो वह या उसके अभिभावक या उसके माता-पिता उसके रिश्तेदार यहां तक उसके प्रशिक्षक उन्हें कहीं से पैसा उधारी लेकर सर्वश्रेष्ठ खेल सामग्री, पोशाक उपलब्ध कराते हैं। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई ऐसे खिलाड़ी

हैं जिनके माता-पिता, अभिभावक, दूरों के घर झाड़ू, पोछा करते हैं। आठो रिक्शा चलाते हैं। कुली का काम करते हैं। खोमचा-ठेला लगाकर फल बेचते हैं या गुप्चुप, आलू टिक्का, मोमोस, इडली, दोसा, चाय आदि बेचकर बच्चे का भविष्य बनाने के लिए अपनी गाड़ी मेहनत के पैसा से बच्चों को खेल में आगे बढ़ने की चाहत को पूरा करते हैं। परंतु यह दुर्भाग्य की बात है कि समाज के ऐसे वर्ग से आये राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को आज आर्थिक अभाव और बेरोजगारी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा के अभाव में वे अभावग्रस्त, निचले, तबके के खिलाड़ी दर-दर की टोकर खा रहे हैं। पिछले दस वर्षों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकार आई व चली गई परंतु नीति निर्धारण करने वाले प्रशासनिक अधिकारी तो वही हैं। वस्तुतः ऐसे ही अधिकारियों से पूछ परख होनी चाहिए कि खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का लाभ समय रहते किस कारण से नहीं दिया, और अपने कर्तव्य का पालन ठीक से क्यों नहीं किया? कई उत्कृष्ट खिलाड़ियों के खेलने की उम्र निकल गई आखिर उसके जिम्मेदार भी ये ही अधिकारी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों की लापरवाही से छत्तीसगढ़ में आज सैकड़ों बच्चे, किशोर तथा युवाओं के मन मस्तिष्क में खेलकूद के प्रति लगाव कम हुआ है। चर्चा तो यह भी है कि उधारी लेकर या ऋण लेकर बच्चों को खेल में आगे बढ़ाने वाले माता पिता और अभिभावक भी अब अपने नन्हें मुन्नों को खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने से हिचकिचा रहे हैं।

नगरीय निकायों को मरम्मत-संधारण के लिए 22.6 करोड़ की आपात निधि जारी

रायपुर, 25 जून, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को मरम्मत और संधारण कार्यों के लिए 22 करोड़ 6 लाख रुपए की आपात निधि जारी की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर संचालनालय ने सभी निकायों को राशि हस्तांतरित कर दी है। विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जून के लिए यह राशि निधि के अंतर्गत जारी की गई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने मरम्मत-संधारण आपात निधि के अंतर्गत के 14 नगर निगमों को कुल 13 करोड़ 76 लाख रुपए जारी किए हैं।

केंद्रीय गौड महासभा ने रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

उत्तर, 25 जून। चन्देले की बेटी गोंडवाना की रानी चण्डी थी महचण्डी थी वह दुर्गावती भवानी थी और भारतीय इतिहास की वीरंगना रानी दुर्गावती की आज 462वीं बलिदान दिवस मनाया गया केन्द्रीय गौड महासभा धर्मशास्त्र एवं तहसील इकाई दुर्गा व मुंडा परिक्षेत्र बरेला दुर्गा के तत्वबोधन में कचन धुवा देवालय सिविल लाईन दुर्गा में रानी दुर्गावती के प्रतिमा पर पूजा अर्चना श्रीफल तोड़कर माल्यार्पण किया तत्पश्चात रानी दुर्गावती की जय घोष कर नारे लगाए उसके पश्चात समाज प्रमुख केन्द्रीय गौड महासभा धर्मशास्त्र एवं तहसील इकाई मुंडावी ने रानी दुर्गावती जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किए गए समाज



हित एवं देश हित के लिए कार्य इसमरण करायें तत्पश्चात तहसील उपाध्यक्ष बहदुर सिंह नेताम ने रानी दुर्गावती ने मुगल साम्राज्य से किस प्रकार लड़ाई वह लड़ते हुए अपनी आन बान और शान की लड़ाई लड़ते हुए अपनी ही कटार अपनी छाती पर कटार धोष कर अपनी प्राण त्याग दिये मगर दुश्मन के साथ नहीं लगी ऐसी ही वीरंगना रानी दुर्गावती थी मातृशक्ति की ओर से उठा टाकुर उपाध्यक्ष ने भी संबोधित की तत्पश्चात मुंडा परिक्षेत्र बरेला में भी रानी दुर्गावती की बलिदान दिवस पर महिलाओं और बच्चों के लिए कुर्सी दौड़ गोली चम्मच जलेबी दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित

की गई इस अवसर पर केन्द्रीय गौड महासभा धर्मशास्त्र एवं तहसील इकाई मुंडावी जी महासचिव गौरे लाल टाकुर कोषाध्यक्ष धनेश्वर धुवं तहसील अध्यक्ष चुरामन कतलम महावीर टाकुर बंसत टाकुर पूर्व तहसील अध्यक्ष गजराज नेताम तुलसी टाकुर मनहरण टाकुर नोबिल टाकुर श्रीमती उषा टाकुर उपाध्यक्ष तामेश्वरी टाकुर ममता टाकुर श्यामा टाकुर उषा धुवं कुमारी होमाश कुंजाम शिवकुमारी मरकाम प्रभा मरकाम तहसील उपाध्यक्ष बहदुर सिंह नेताम और समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे अंत में खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए उन्हे समाज के द्वारा सम्मानित किए और सभी अपील की समाज सभी को एक लेकर चले प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को आगे बढ़ाने सहयोग करें।

महिला से शादी व तबादले के नाम पर युवक ने की 60 हजार रुपए की ठगी

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 25 जून। रायपुर निवासी आरोपी द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर एवं उसका स्थानांतरण करा दिए जाने का झांसा देकर 600000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 318 (4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता सुभमा टाकुर निवासी नयापरा 36 वर्ष शासकीय प्राथमिक शाला नवागांव विकासखंड धमधा जिला दुर्गा में पदस्थ है। उसके पति राजेंद्र कुमार टाकुर का 24 अक्टूबर 2024 को स्वर्गवास हो गया है। वह अपनी सास एवं दो नाबालिग बच्चों के साथ रहती है। 23 मई 2026 को जीवनसाथी एप के माध्यम से एक मोबाइल धारक अर्जुन कसेर नामक व्यक्ति से उसकी मोबाइल पर बातचीत हुई। अर्जुन कसेर ने कहा कि मैं भी तलाकशुदा हूँ और सिंचाई विभाग में क्लर्क के पद पर नौकरी करता हूँ। मैं भी दूसरी शादी करना चाहता हूँ। आप मेरे से शादी करोगी क्या इस के बाद लगातार अर्जुन कसेर पीड़िता को फोन करके बार-बार झांसा देने लगा कि तुम्हारा स्थानांतरण शासकीय प्राथमिक शाला नवागांव पुरदा से रायपुर के आसपास 15 किलोमीटर के दायरे में करवा दूंगा। 7 लाख रुपए लगेगा

और तुम्हारा स्थानांतरण हो जाएगा अर्जुन ने कहा कि किसी भी तरह उसे 6 लाख रुपए दे दो, एक लाख में स्वयं मिलाकर तुम्हारा स्थानांतरण धमधा से रायपुर के आसपास हो जाएगा। इसके बाद दोनो तुमसे शादी कर लूंगा और दोनो पति-पत्नी की तरह रहेंगे। पीड़िता सुभमा टाकुर ने पैसे दे दिए शंका होने पर पीड़िता ने 4 जून को अर्जुन कसेर को मोबाइल पर कॉल की और कहा कि आपने तलाकशुदा होने की झूठी जानकारी दी, नौकरी करने की झूठी बात कही, मेरा स्थानांतरण करने की बात कह कर मुझे धोखा दे रहे हो। मैं अब तुमसे शादी नहीं करूंगी और ना ही मुझे स्थानांतरण करवाना है। मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। इस पर आरोपी टालमटोल करता रहा पीड़िता ने मांगे तलाक के कागज व ज्वेलिंग लेटर वहीं 1 जून को पीड़िता सुभमा टाकुर ने अर्जुन कसेर से कहा कि तुम तलाकशुदा हो तो तलाक प्रमाण पत्र दिखाओ और व्हाट्सएप पर उसे भेजो वहीं अपनी सिंचाई विभाग नौकरी क्लर्क पद जॉइनिंग आदेश कॉपी मेरे पिताजी के पास है। मैं बाद में भेजूंगा। पीड़िता द्वारा बार-बार तलाक प्रमाण पत्र एवं नौकरी ज्वेलिंग आदेश कॉपी मांगने पर आरोपी टाल मटोल करते रहा

एक नजर

ट्रैफिक पुलिस ने 107 वाहनों का चालान किया

भिलाई, 25 जून (तहस.)। राष्ट्रीय राजमार्ग पर नो-पार्किंग में खड़े 107 वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने ई-चालान की कार्रवाई की। पुलिस ने गाड़ियों को जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है राष्ट्रीय ट्रैफिक एएसपी ब्रज मिश्रा ने बताया कि जिले में सुरक्षित एवं सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राजमार्ग एवं शहर के व्यस्त क्षेत्रों में नो-पार्किंग अभियान चलाकर सड़क व हाइवे पर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों को सख्त जांच की गई। अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत ई-चालान जारी कर कार्रवाई की गई। बाजार में भी चल्ती ई-चालानी अभियान ट्रैफिक एएसपी ने बताया कि इसके अतिरिक्त शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों व व्यस्त मार्गों में विशेष जांच अभियान चलाकर आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। आगे बाजारों में नो-पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ भी ई-चालानी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और आम नागरिकों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले सम्मानित



भिलाई, 25 जून (तहस.)। जिला दुर्गा डायल 112 में पदस्थ कर्मचारियों एवं चालकों की बैठक आयोजित की गई बैठक में डायल 112 के माध्यम से प्राप्त होने वाले इवेंटों पर त्वरित, प्रभावी एवं संवेदनशील कार्रवाई सुनिश्चित करने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए बैठक के दौरान ग्रामीण एवं शहरी थाना क्षेत्रों में संचालित ईभारत वाहनों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई तथा घटनास्थल पर समयबद्ध पहुंचकर पीड़ितों को तत्काल सहायता उपलब्ध करना, आम नागरिकों से शालीन व्यवहार रखने, आपातकालीन परिस्थितियों में बेहतर समन्वय स्थापित करने एवं सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु निर्देश दिए गए साथ ही सी-4 रायपुर से प्राप्त इवेंटों में उत्कृष्ट कार्य कर समय पर सहायता पहुंचाने वाले डायल 112 के स्टाफ कर्मचारियों एवं चालकों को उत्साहवर्धन हेतु कैश रिवाइड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया दुर्गा डीआईजी विजय अग्रवाल ने कहा कि डायल 112 पुलिस और आमजन के बीच त्वरित सहायता का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रत्येक कर्मचारी एवं चालक अपने दायित्व का निर्वहन पूर्ण संवेदनशीलता, तत्परता एवं अनुशासन के साथ करें किसी भी आपात स्थिति में समय पर पहुंचकर पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

पिता की हत्या के मामले में पुत्र गिरफ्तार



भिलाई, 25 जून (तहस.)। दुर्गा बोरी थाना क्षेत्र के पारिवारिक विवाद के बाद आरोपी बेटे द्वारा पिता की हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है इस मामले में खास बात यह रही की बेटे ने ही हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद खुद थाना पहुंचकर पिता की मौत हो जाने की सूचना दी थी। पीएम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने शक के आधार पर बेटे को पूछताछ में लिया। बेटे ने अपना अपराध स्वीकार किया। बोरी पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ धारा 103(1), 238 के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में पेश किया है बोरी पुलिस ने बताया कि 17 जून को 19 वर्षीय नीलकमल साहू ने बोरी थाना में पहुंचकर सूचना दी थी। सूचना देते समय नीलकमल ने बताया था कि उसके पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते थे और परिवार से अलग रहते थे तथा दो महीने पहले पारिवारिक विवाद के बाद परिवार के अन्य सदस्य रिश्तेदारों के घर चले गए थे। मामले में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने बहनता से जांच की और उन्हें कई अहम सुचुराग मिले। इनको यह भी जानकारी मिली कि कुलुधर साहू एवं उसके पुत्र नीलकमल साहू के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था विवाद के दौरान आरोपी ने अपने पिता के साथ मारपीट की थी पुलिस में संदेह के आधार पर मृतक के बेटे नीलकमल साहू को पूछताछ में लिया।

एनडीए और आईआईटी तक पहुंची सेक्टर-10 स्कूल की प्रतिभा

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 25 जून। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर.10 में बुधवार को आयोजित सम्मान समारोह में अटल टिकरिंग लैब एटीएल के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और उनके मेंटरों को उनकी नवाचारपूर्ण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में महाप्रबंधक शिक्षा सुश्री शिखा दुबे उपस्थित रहीं। उनके साथ महाप्रबंधक प्रभारी सम्पर्क प्रशासन एवं जनसंपर्क अमृत्यु प्रियदर्शी, उप महाप्रबंधक श्रीमती अर्पणा चंद्रा, सहायक महाप्रबंधक जवाहर बाजपेयी तथा उप प्रबंधक सुश्री शालिनी चौरसिया सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि एटीएल के पूर्व सदस्य और वर्तमान में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए चर्यनित नेत्रांश साहू तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में चर्यनित कुणाल देवांगन ने विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। एटीएल के मेंटर एवं वरिष्ठ व्याख्याता तरुण कुमार साहू



ने विद्यार्थियों द्वारा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में हासिल उपलब्धियों की जानकारी दी। अपने संबोधन में सुश्री शिखा दुबे और अमृत्यु प्रियदर्शी ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज के युवा केवल साहू तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक भी बनें। इस अवसर पर अभिजय चौधरी अलौकिक चौधरी और अमीन खान को उनके

उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वहीं एटीएल के मेंटर तरुण कुमार साहू को विद्यार्थियों के मार्गदर्शन और नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विशेष सम्मान प्रदान किया गया। महाप्रबंधक शिक्षा सुश्री शिखा दुबे तथा स्कूल की प्राचार्य सुश्री सुमिता सरकार को भी विद्यार्थियों के मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए प्रशंसा प्रमाण-पत्र दिए गए। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती अर्पणा चंद्रा ने किया। जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य सुश्री सुमिता सरकार ने प्रस्तुत किया।

पावर हाउस रेलवे स्टेशन के सामने फैला कबाड़ जल



भिलाई, 25 जून। नगर निगम द्वारा शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से फैलाई गई कबाड़ सामग्री के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जून-3 मदर टेरसा नगर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 36 में निगम

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थल पर फैलाई गई कबाड़ सामग्री को जब्त किया। जानकारी के अनुसार पावर हाउस रेलवे स्टेशन के सामने स्थित जगदम्बा स्वीट्स के पास कुष्ठ कबाड़ियों द्वारा बंद पैमाने पर कबाड़ एवं कचरा सामग्री फैला कर रखी गई थी। शिकायत मिलने पर निगम अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया, जहां पाया गया कि फैली हुई सामग्री के कारण क्षेत्र की स्वच्छता प्रभावित हो रही थी और आम नागरिकों व राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए निगम की टीम ने संबंधित कबाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई कर कबाड़ सामग्री जब्त की। इस दौरान जेन स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक तथा राजस्व विभाग के उपपरवाइजर सहित निगम का अमला उपस्थित रहा। नगर निगम का कहना है कि स्वच्छ भिलाई के निर्माण के लिए नियमित निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

झुका हुए साइन बोर्ड से हादसे की आशंका, निगम से कार्रवाई की मांग

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 25 जून। शिवसेना (यूबीटी) भिलाई जिला अध्यक्ष राजू गुप्ता ने प्रेस विज्ञापि जारी कर नगर निगम प्रशासन का ध्यान पावर हाउस चौक से नदिनी रोड जाने वाले मार्ग पर लगे एक क्षतिग्रस्त यातायात साइन बोर्ड की ओर आकर्षित करवाया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा लगाया गया यातायात सुरक्षा निर्देश देने वाला साइन बोर्ड हल ही में आए ऑर्भी-तूषण के कारण एक ओर झुक गया है। यह बोर्ड सड़क की दिशा में झुका हुआ है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। राजू गुप्ता ने कहा कि जिस दिशा में साइन बोर्ड झुका हुआ है, उसके ठीक पास से विद्युत तार भी गुजर रहे हैं। तेज हवा या बारिश के दौरान बोर्ड के बिजली तारों से टकराने की संभावना से इनकार नहीं किया जा



नौसेना के 3 अत्याधुनिक जहाजों को बनाने में सेल के विशेष स्टील का उपयोग किया गया



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 25 जून। महारल कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ाने में एक बार फिर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कंपनी ने हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए तीन अत्याधुनिक जहाजों-आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक-के निर्माण के लिए लगभग 5,700 टन विशेष रक्षा-ग्रेड स्टील की आपूर्ति की है। इन तीनों जहाजों को 21 जून को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। यह उपलब्धि भारत की समुद्री सुरक्षा और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सेल ने इन युद्धपोतों के निर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली डीएमआर 249 ए ग्रेड हॉट-रोल शीट एवं प्लेट उपलब्ध कराई। इस विशेष रक्षा-ग्रेड स्टील का उत्पादन कंपनी के बोकारो, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों में किया गया। सेल इससे पहले देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रान्त तथा प्रोजेक्ट-17 ए के स्टील फ्रेमवर्क आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमागिरी और आईएनएस उदयगिरि के निर्माण में भी विशेष स्टील उपलब्ध करा चुका है। इसके अलावा आईएनएस अजय, आईएनएस निस्तार और आईएनएस अंजदीप जैसे महत्वपूर्ण नौसैनिक प्लेटफॉर्मों में भी सेल के स्टील का उपयोग किया गया है। सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. अशोक कुमार पंडा ने कहा कि कंपनी भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सीएम हेल्पलाइन और ई-ऑफिस के प्रभावी संचालन की बैठक में की गई समीक्षा



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 25 जून। नगर निगम सीएम हेल्पलाइन 1076 और ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आयुक्त राजीव कुमार पांडेय की उपस्थिति में निगम सभागार में आयोजित बैठक में मुख्य कार्यालय एवं सभी जोन कार्यालयों के अधिकारी, लिपिक और कम्प्यूटर ऑपरेटर शामिल हुए। बैठक के दौरान सीएम

हेल्पलाइन पोर्टल एवं ई-ऑफिस प्रणाली के संचालन में आ रही तकनीकी और प्रक्रियागत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर उनके समाधान पर विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों को बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। आयुक्त राजीव कुमार पांडेय ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया

रखते हुए उक्त साइन बोर्ड की तत्काल मरम्मत अथवा उसे सुरक्षित रूप से हटाने की कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके।

शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने जिला प्रशासन की कार्रवाई कर रहा

दुर्गा, 25 जून। कलेक्टर अभिजित सिंह के निर्देशन में शासकीय संपत्तियों की सुरक्षित रखने और अवैध कब्जों को हटाने विधि सम्मत कार्रवाई जारी है। इसी तारतम्य में मुस्लीदी का परिचय देते हुए धमधा तहसील अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शासकीय आबादी भूमि को अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त कराया गया है। तहसीलदार धमधा श्रीमती मीना साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार, धमधा स्थित शासकीय आबादी भूमि खसरा नंबर 1719/1 के आंशिक भाग (रकबा 1525 वर्गफीट) पर अनावेदक संतु यादव रिफा क्रांति यादव द्वारा अतिक्रमण रूप से टिन शेड लगाकर अतिक्रमण किया गया था। इस शिकायत पर त्वरित संत्रान लेते हुए राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार जांच व सुनवाई की गई तथा अनावेदक के विरुद्ध बेदखली आदेश पारित किया गया।

निधन

ए.सी. छबलानी भिलाई, 25 जून। सिंधी ब्रादर मंडल के संरक्षक एवं भिलाई इस्पात संयंत्र से सेवानिवृत्त उप म हा.प.ब.ध.क. ए.सी. छबलानी का निधन हो गया। उनके

निधन से सिंधी समाज एवं सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। हुडको निवासी छबलानी लंबे समय तक भिलाई इस्पात संयंत्र में सेवाएं देने के साथ-साथ सामाजिक एवं सामुदायिक गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे। उनका अंतिम संस्कार राधेगुरु मुक्तधाम में किया गया। सिंधी ब्रादर मंडल के अध्यक्ष जय कुमार अम्बानी ने छबलानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी

समाचार

संक्षेप

जिला अस्पताल के डायलिसिस केंद्र से मिल रही किडनी मरीजों को मदद, अब तक 14 हजार से अधिक सेशन



तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

अधिकारी डॉ राजेश अवस्थी ने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत जिले में यह सुविधा उपलब्ध है जो पूरी तरह निःशुल्क है। 25 जून को अस्पताल में नए किडनी मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा ऑनलाइन परामर्श दिया जाएगा। जरूरतमंद मरीज इसका लाभ ले सकते हैं। अस्पताल में अपनी डायलिसिस करवाने आए भाटापापा के ग्राम गोगिया निवासी सुनील कुमार ने बताया कि यह उनका केंद्र में पहला सेशन है। इससे पहले दो सेशन उन्होंने बिलासपुर के निजी अस्पताल से लिया था जहाँ हर हफ्ते 7-8 हजार लग जाता था। जिला अस्पताल में यह निःशुल्क है जिससे उन्हें काफी राहत मिली है।

रेलवे पार्किंग में लोगों से की जा रही है मनमाने राशि की वसूली



5 मिनट देरी पर भी वसूला जा रहा पूरा शुल्क, नक्सल पीड़ित परिवारों को धमकी देने का आरोप

तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

डोंगरगढ़, 25 जून। रेलवे स्टेशन परिसर पर स्थित पार्किंग की व्यवस्था को लेकर नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवारों में आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि पार्किंग संचालक द्वारा वाहन पार्किंग के समय में मामूली देरी होने उबल शुरू करवाते हैं। पार्किंग के लिए धमकी देकर पैसा वसूला गया। नाराज नक्सल पीड़ित परिवार अब रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर पार्किंग व्यवस्था बंद करने और मनमानी पर रोक लगाने की मांग करेंगे। पीड़ित परिवार की मांग है कि, यात्रियों से लूट बंद हो, पार्किंग व्यवस्था में पारदर्शिता हो और दोषियों पर कार्रवाई हो।

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में छग राज्य सहकारी उत्पाद की दुकान का शुभारंभ

मरीजों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती सुविधाएं

तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

राजनांदगांव, 25 जून। मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी उत्पाद की दुकान का विधिवत उद्घाटन उत्साहपूर्ण वातावरण में संघर्ष हुआ। इस अवसर पर समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक दिलीप शुक्ला, चिन्मय पाठक सहित बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमूह ने इस महत्वपूर्ण पहल के साक्षी बनकर आयोजन की गरिमा बढ़ाई। अस्पताल परिसर में उत्पाद की दुकान प्रारंभ होने से मरीजों, उनके परिवारों तथा आम नागरिकों को आवश्यक वस्तुएं एक ही स्थान पर सहज एवं उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकेंगी। यह पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सहयोग प्रदान करेगी, बल्कि सहकारिता के माध्यम से जनसुविधाओं के विस्तार का भी उत्कृष्ट उदाहरण बनेगी। उद्घाटन अवसर पर वक्तव्यों में कहा कि अस्पतालों में आने वाले मरीज एवं उनके परिवार अक्सर आवश्यक सामग्री की उपलब्धता के लिए भटकते हैं। ऐसे में सहकारी उत्पाद की दुकान उनकी जरूरतों को पूरा करने के साथ समय और धन दोनों की बचत करेगी। साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलने से चिन्मय पाठक सहित बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमूह ने इस महत्वपूर्ण पहल के साक्षी बनकर आयोजन की गरिमा बढ़ाई। अस्पताल परिसर में उत्पाद की दुकान प्रारंभ होने से मरीजों, उनके परिवारों तथा आम नागरिकों को आवश्यक वस्तुएं एक ही स्थान पर सहज एवं उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकेंगी। यह पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सहयोग प्रदान करेगी, बल्कि सहकारिता के माध्यम से जनसुविधाओं के विस्तार का भी उत्कृष्ट उदाहरण बनेगी। उद्घाटन अवसर पर वक्तव्यों में कहा कि अस्पतालों में आने वाले मरीज एवं उनके परिवार अक्सर आवश्यक सामग्री की उपलब्धता के लिए भटकते हैं। ऐसे में सहकारी उत्पाद की दुकान उनकी जरूरतों को पूरा करने के साथ समय और धन दोनों की बचत करेगी। साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलने से चिन्मय पाठक सहित बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमूह ने इस महत्वपूर्ण पहल के साक्षी बनकर आयोजन की गरिमा बढ़ाई। अस्पताल परिसर में उत्पाद की दुकान प्रारंभ होने से मरीजों, उनके परिवारों तथा आम नागरिकों को आवश्यक वस्तुएं एक ही स्थान पर सहज एवं उचित मूल्य

सात बच्चों को कोख में खोने के बाद डॉ. सुरभि मोहबे ने दिलाया मातृत्व सुख

तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

राजनांदगांव, 25 जून। डॉ. सुरभि मोहबे हॉस्पिटल कंचनबाग, डी माट रोड की संचालक एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सुरभि ने एक नायाब कार्य कर ग्रामीण महिला को लंबे समय बाद मातृत्व सुख का आनंद दिलाया है। प्रसूती ने इसके पूर्व सात बच्चों को अपनी कोख में ही खो दिया था। 16 वर्ष पूर्व वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद से वह इस सुख के लिए तैयार रही थी। इस आठवें गर्भ की स्थिति में भी वही बी पी की समस्या बनी हुई थी। डॉ. सुरभि ने बड़ी सावधानी पूर्वक इलाज करते हुए स्वस्थ बच्चे का जन्म कराया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वास्थ्यगत सुविधा और नायाब कार्यप्रणाली द्वारा डॉ. सुरभि मोहबे ने एक महिला को मातृत्व सुख प्रदान कर न केवल साहू परिवार का दिल जीत लिया वरन उस परिवार में लक्ष्मी रूपी कन्या का जन्म भी कराया। गौरतलब है कि जिले के



छुरिया ब्लॉक के ग्राम झीतराटोला निवासी लीला साहू विगत 16 वर्षों से संतान सुख से वंचित थीं। खुद लीला साहू बताती हैं कि उन्होंने गर्भधारण तो किया किंतु हर बार उनकी ब्लड प्रेशर की बीमारी ने उनके सपनों को पूरा नहीं होने दिया। हर बार गर्भ की स्थिति में हाई ब्लड प्रेशर के कारण उनके साथ बच्चों ने दुनिया नहीं देख पाई। मातृत्व सुख प्रदान कर न केवल साहू परिवार का दिल जीत लिया वरन उस परिवार में लक्ष्मी रूपी कन्या का जन्म भी कराया। गौरतलब है कि जिले के

आयुक्त ने नाला सफाई का जायजा लेकर समुचित सफाई करने के दिये निर्देश

तुलसीपुर नाली निर्माण देख पानी निकासी के लिए पर्याप्त ढाल रखने कहा

तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

राजनांदगांव 25 जून। शहर की ड्रेन व्यवस्था सुचारू रूप से चले एवं बारिश में पानी भरान व अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो यह सुनिश्चित करने नगर निगम द्वारा बरसात के पूर्व शहर के बड़े एवं प्रमुख नालों एवं पानी भरान स्थल की सफाई युद्ध स्तर पर कराई गयी है और वर्तमान में दुजरे चरण की सफाई जारी है। आने आयुक्त अतुल विश्वकर्मा प्रातः सफाई व्यवस्था देखने की कड़ी में शहर में चल रहे नाली नालों की सफाई का निरीक्षण कर पानी भरान

क्षेत्रों में साफसफाई कर पानी निस्तारी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये, ताकि बारिश का पानी बाड़ों में न भरे। आयुक्त विश्वकर्मा आज प्रातः शहर के इंदिरा नगर, गंज चैक, गोल बाजार में सफाई व्यवस्था का जायजा लेकर इंदिरा नगर एवं गंज चैक में चल रहे नाला सफाई देख कहा कि नाला के निचले स्तर से कचरा निकाले, नाली में लगे जाली निकालने कहा ताकि पानी का सुचारू बहाव हो। उन्होंने कहा कि सभी नालों को अच्छे से सफाई की जाए, जिन नालों की सफाई चल रही है वह उन नालों की बारिश के पानी की समुचित निकासी

के आधार पर सफाई करना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि पानी भरान क्षेत्र के नाली नालों की भी अच्छी तरीके से सफाई की जाए। नाला सफाई में आ रही बाधा को भी दूर कर सफाई करें, ताकि उस क्षेत्र में बारिश का पानी न भरे। आयुक्त विश्वकर्मा ने गोल बाजार का निरीक्षण कर बाजार क्षेत्र के नाली की प्रतिदिन सफाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सब्जी पसरा वालों को नाली में कचरा न डालने, गंदगी न फैलाने समझाई देवे, नाली में कचरा जाने से पर्याप्त बहाव के अभाव में बारिश का पानी बाजार में भर जायेगा, जिससे निजात दिलाना

है। उन्होंने बाजार के आकाशी शौचालय को जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार तुलसीपुर में निर्माणधीन नाली का जायजा लेकर काम में तेजी लाकर समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नाली निर्माण में ढलान का विशेष ध्यान रखा जाए जिससे पानी की पर्याप्त निकासी हो सके। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। किसी भी क्षेत्र में बारिश का पानी न भरे इसके लिए अभी से चिन्हांकित कर सफाई कराना सुनिश्चित करे।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनांतर्गत जियं सदस्यों को दिया गया प्रशिक्षण

बालोद, 25 जून (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनांतर्गत 18 से 19 जून 2026 तक जिला पंचायत संसाधन केन्द्र बालोद में जिला पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्यों का 'पंचायत विकास योजना सह पंचायत उन्नति सूचकांक' विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में जिला पंचायत के सभी नवनिर्वाचित सदस्य उपस्थित हुए।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार चंद्रवंशी के निर्देशानुसार विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को 16वें वित्त आयोग की नवीन गाइडलाइन के अनुसार पंचायत विकास योजना, पंचायत विकास सूचकांक सहित शासन की महत्वाकांक्षी योजना ठोस अपशिष्ट नियम 2026, वीबी जी राम जी के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उक्त प्रशिक्षण का संचालन उपसंचालक पंचायत काव्या जैन की उपस्थिति में किया गया।

एक नजर

अशांति फैलाने वाले बदमाशों पर धारा 170 के तहत की गई कार्रवाई



चिखली, 25 जून (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। पुलिस अधीक्षक सुशील अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे सतत अभियान के तारतम्य में बदमाश 01. संदीप पटेल पिता स्व. संतराम पटेल उम्र 30 साल साकिन मोतीपुर वार्ड नं. 03 पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव छग., 02. छथिलाल निर्मलकर पिता स्व. जगन्नाथ निर्मलकर उम्र 26 साल साकिन मोतीपुर वार्ड नं. 08 काई तालाब के पास पुलिस चौकी चिखली, 03. शुभम यादव पिता रेखू यादव उम्र 27 साल साकिन चिखली रमन बाजार पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव के द्वारा वाद विवाद कर शांति व्यवस्था भंग कर अप्रिय घटना घटित होने के संभावना पर बदमाशों के विरुद्ध पृथक-पृथक धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय राजनांदगांव पेश किया किया गया। उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, म.प्र.आर. वंदना पटले, आर. चन्द्रकूपर आयाम, सुनील बेरागी, आदित्य सोलंकी एवं चौकी चिखली स्टाफका महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा है।

गरीबों को पट्टा प्रदान कर आवास का लाभ देना मोदी सरकार की जनहितकारी योजना : कर्माजीया

डोंगरगढ़, 25 जून (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष



रामकृष्ण कर्माजीया ने केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा गरीब परिवार को पट्टा प्रदान कर आवास योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा का आभार प्रकट करते बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 8 मई 2026 को जारी किए पत्र में राज्य के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में 2017 से भूमि पर काबिज आवासहीन व्यक्ति को पट्टा प्रदान किए जाने की घोषणा के साथ राज्य के समस्त जिलाधीशों को 15 अगस्त 2026 तक छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टा प्रदान अधिकार नियम 2023 के अंतर्गत सर्वे की कार्यवाही पूर्ण कराने अधिसूचित किया गया है।

वहीं राज्य शासन द्वारा इन नियमों के अंतर्गत जिले के समस्त नगरीय निकायों में सर्वे की कार्यवाही किया जाना है। सर्वे की कार्यवाही हेतु समुचित संख्या में राजस्व एवं नगरीय निकायों के अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए, सर्वेक्षण दल का गठन किया जाना है। छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टा प्रदान अधिकार नियम 2023 में विहित प्रक्रिया एवं प्रावधान अनुसार सर्वे की कार्यवाही कर निर्धारित प्ररूप-क (नियम-3) में जानकारी

बारिश पूर्व अभियान के तहत शहर के छोटे-बड़े नालों एवं नालियों की सफाई गैंग एवं जेसीबी से की जा रही

निगम ने सफाई, जल निकासी, सौंदर्यीकरण, सड़क मरम्मत का काम तेज किया

आंधी-बारिश के कारण 33/11 केवी सब स्टेशन में आंधी तकनीकी खराबी को ठीक कर मोहरा जल संयंत्र में विद्युत आपूर्ति की गई बहाल

नगर निगम ने नागरिकों से शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने, नालियों में कचरा न डालने तथा पौधों के संरक्षण में सहयोग की अपील की

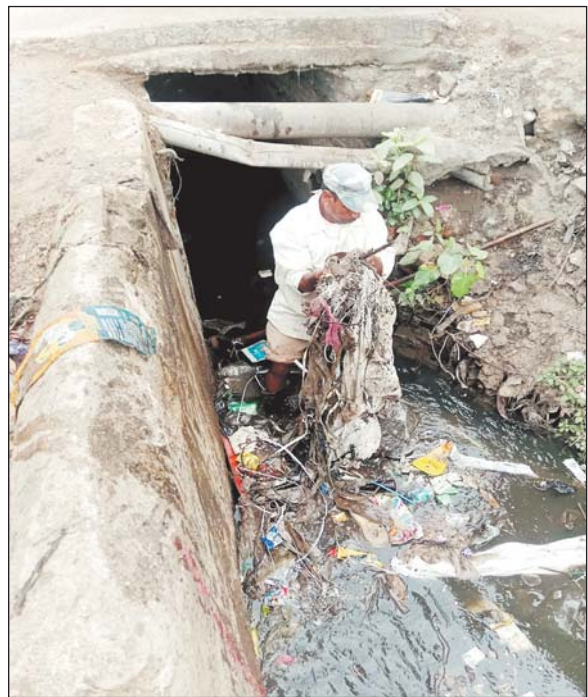
तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

राजनांदगांव 25 जून। नगर पालिका निगम राजनांदगांव द्वारा शहर में स्वच्छता, जल निकासी, सड़क मरम्मत, पौधों के संरक्षण तथा सौंदर्यीकरण कार्यों को प्राथमिकता के साथ संचालित किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों पर कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

सफाई एवं जल निकासी

व्यवस्था: नगर निगम के स्वास्थ्य अमला द्वारा नियमित रूप से फ्लाईओवर के नीचे एवं शहर के विभिन्न बाड़ों की साफसफाई की जा रही है। आंधी-तूफान के कारण फ्लाईओवर के नीचे फैले सूखे पत्तों एवं कचरे की सफाई कर दी गई है। बारिश पूर्व अभियान के तहत शहर के छोटे-बड़े नालों एवं नालियों की सफाई गैंग एवं जेसीबी मशीनों के माध्यम से की जा रही है। प्रथम चरण की सफाई पूर्ण होने के बाद शेष नालों की द्वितीय चरण में सफाई जारी है। कलेक्टरेट परिसर की नालियों में आंधी-तूफान के कारण पत्ते जमा होने से अवरोध उत्पन्न हुआ था, जिसे प्राथमिकता से साफकिया जा रहा है। डॉक्टर कॉलोनी, बलदेव बाग तथा अन्य जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में भी नालियों की सफाई की जा रही है। नालियों पर हुए अतिक्रमणों को हटाने की सफाई भी प्रस्तावित है।

कार्डकों के रखरखाव एवं मरम्मत की तैयारी: निगम निगम के स्टेशनपारा से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क सहित शहर की कई



पुरानी सड़कों का डामरीकरण प्रस्तावित है। वर्तमान में डामर उपलब्ध नहीं होने से कार्य प्रभावित हुआ है। संबंधित ठेकेदारों को कार्य शीघ्र प्रारंभ करने निर्देश जारी किए गए हैं। डामर उपलब्ध होते ही सड़कों

में पेचवर्क एवं मरम्मत कार्य कराया जाएगा। मोहरा-सिंगदई मार्ग, कलेक्टरेट गार्डन के समीप सर्विस रोड, गौरव पथ तथा अन्य स्थानों पर सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं। बाड़ों में सीसी रोड एवं नाली निर्माण के लिए पार्षदों से प्रस्ताव आमंत्रित कर शासन को भेजे गए हैं। हरित क्षेत्र एवं पौधों के संरक्षण पर विशेष ध्यान: शहर के डिवाइडों एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए पौधों को गर्मी से बचाने के लिए नियमित रूप से टैकरों के माध्यम से सिंचाई की जा रही है। कलेक्टरेट परिसर एवं अन्य क्षेत्रों में झुके हुए पौधों को पुनः व्यवस्थित किया जा रहा है तथा बड़े वृक्षों की आवश्यक छटाई भी की जा रही है। आगामी वर्षा ऋतु में पौधरोपण के लिए सुपरिचित स्थलों का चयन किया जा रहा है।

सौंदर्यीकरण कार्यों को मिलेगी गति : शहर के प्रमुख चौक-चौराहों एवं डिवाइडों के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव शासन को

भेजा गया है। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद सौंदर्यीकरण कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। रानी सागर एवं बूढ़ा सागर क्षेत्र में पूर्व में असाामाजिक तत्वों द्वारा क्षति पहुंचाए जाने के मामलों में एफ्बाईआर दर्ज कराई गई थी। शासन के बजट में उक्त क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए प्रावधान किया गया है। लक्ष्मण झूला की मरम्मत प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है तथा शीघ्र ही इसे पुनः शुरू किया जाएगा।

जलापूर्ति एवं विद्युत व्यवस्था बहाल: आंधी-बारिश के कारण 33/11 केवी सब स्टेशन में आंधी तकनीकी खराबी के कारण विद्युत आपूर्ति प्रभावित होने से मोहरा जल संयंत्र की बिजली बाधित रही है। विशेष समय पर ठीक कर लिया गया। विद्युत आपूर्ति बहाल होने के बाद टिकियों को भरकर नियमित जलापूर्ति पुनः शुरू कर दी गई है। मोहरा सर्विस रोड की स्टीट लाइटें भी शॉर्ट सर्किट के कारण बंद हो गई थीं, जिन्हें निगम के विद्युत अमले द्वारा सुधार दिया गया है।



कमाई के लिए अवैध और वैध का खेल चलता रहता है

निगम क्षेत्र की जल आपूर्ति व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। टेल एंड तक वैध नलों वालों घर तक पानी नहीं पहुंचता है। इससे हर साल निगम क्षेत्र में पानी की समस्या बनी रहती है। इस तरह देखा जाए तो अवैध नल कनेक्शन तो निगम व निगम क्षेत्र की जनता को नुकसान पहुंचाने वाला काम है। और निगम को नुकसान पहुंचाने वाला यह काम करता कौन है। निगम के कुछ अधिकारी व कर्मचारी करते हैं।सवाल यह भी उठता है कि जब निगम नल का वैध कनेक्शन १० हजार रूपए में देता है तो लोग १४ से १५ हजार रूपए देकर अवैध नल कनेक्शन क्यों लेते हैं। इसकी कई वजहें हो सकती है लेकिन एक वजह तो यही हो सकती है कि वैध कनेक्शन की तुलना में अवैध कनेक्शन जल्दी मिलता है और पानी का पैसा भी नहीं देना पड़ता है।वैध कनेक्शन से निगम के कुछ अधिकारी व कर्मचारी की कोई कमाई नहीं होती है, अवैध नल कनेक्शन से होती है,इसलिए अवैध नल कनेक्शन हर साल दिए जाते हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे निगम क्षेत्र में ९० हजार अवैध नल कनेक्शन हो गए हैं।

नगर निगम को पैसों की जरूरत हमेशा रहती है, वह हमेशा आय के नए स्रोत तलाशती रहती है। वह सोचती रहती है कि पैसा कहां से और कैसे मिल सकता है।ऐसे में निगम को ९० हजार नल कनेक्शन का पता लगने पर लगा होगा कि इसे वैध करके क्यों कुछ कमाई कर

ली जाए।निगम ने निगम अधिनियम १९५६ व फरवरी २०१- के प्रावधानों के अनुसार एक योजना बनाई है।यानी निगम कानूनन अवैध नल कनेक्शनों को वैध करने जा रही है। इसके लिए ९०दिन का समय तय किया गया है। जितने जिन लोगों के नल कनेक्शन अवैध है, उनको ९० दिन के भीतर अपने नल कनेक्शन को वैध करना है। इसके लिए निगम में आवेदन पैसे के साथ देना होगा। इसके लिए नियमित करने का शुल्क ५००० रूपए और वैध नल कनेक्शन का शुल्क २०६८२ रूपए घरेलू कनेक्शन का और व्यवसायिक नल कनेक्शन के लिए १५ हजार रूपए नियमितिकरण शुल्क, व वैध कनेक्शन शुल्क १५६८२ रूपए देना होगा। इस तरह देखा जाए तो अवैध नल कनेक्शन को निगम २० से ३० हजार रूपए में वैध करने जा रहा है।इससे निगम को अच्छी आय हो सकती है।निगम का तर्क हो सकता है कि इससे आम लोगों को भी फायदा है और निगम को भी फायदा है। निगम की आलोचना करने वाले लोग कह सकते हैं। निगम अपनी आय के लिए एक तरह से अवैध नल कनेक्शनों को बढ़ावा दे रहा है। निगम व निगम के लोग दोनों तरह से कमाई कर रहे हैं। पहले निगम के लोग व नल कनेक्शन देने का काम करने वाले ठेकेदार जल्दी नल कनेक्शन देने के नाम पर १४ से १५ हजार रूपए कमाई करते हैं।वह काम कभी बंद नहीं होता है और शहर सरकार

कुछ बरसों में जब अवैध नलों की संख्या बढ़ जाती है तो निगम की कमाई के नाम पर इनको वैध करने का फैसला करती है। इससे निगम की कमाई हो जाती है।यानी निगम के लोग अवैध नल कनेक्शन के नाम पर कमाई करते हैं तो निगम कनेक्शन को वैध करने के नाम पर कमाई करता है। अब सवाल उठता है कि निगम की यह योजना सफल होगी या नहीं होगी। क्योंकि योजना तो सफल तब ही लागी जाएगी जब ९० हजार अवैध नल कनेक्शन को वैध कराने लोग सामने आते हैं।एक गणित के हिसाब से तो अवैध नल कनेक्शन कराने वालों को लग सकता है कि वह १५ हजार रूपए अवैध नल कनेक्शन को दे चुके हैं और २० हजार में नियमित कराते हैं तो नल कनेक्शन ३५ हजार का पड़ता है और वह नया नल कनेक्शन लेते हैं तो उनको दस हजार रूपए देना पड़ेगा। ऐसे में उनको लग सकता है कि अवैध नल कनेक्शन कटता है तो कटे वह नया नल कनेक्शन ले लेंगे तो उनको लग सकता है कि दस हजार रूपए बच रहे हैं, कई लोग यह भी सोच सकते हैं कि जो लोग नल काटने आते हैं उनको ही बाद में नल जोड़ने के लिए कुछ पैसे देकर राखी किया जा सकता है।यानी अवैध कनेक्शन कटेगा जरूर लेकिन बाद में उसे जुड़वाया जा सकता है, इसमें भी कम पैसा लींगा।इससे सम्झना जा सकता है कि बहुत सारे लोग अगर अवैध नल कनेक्शन को वैध करवा सकते हैं तो बहुत सारे लोग अवैध कनेक्शन से बदस्तुर अपना काम चला सकते हैं और ऐसा होना संभव इसलिए है कि निगम में ऐसे अवैध काम आसानी से होते हैं।बच कुछ पैसे खर्च करने होंगे।

विश्लेषण

नरेन्द्र मोदी सबसे लंबे समय तक ‘प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित’ प्रधानमंत्री

सुश्री शर्मिष्ठा मुखर्जी

भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता को लेकर चल रही बहस के बीच, मुझे मेरे पिता, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अभूतपूर्व जीत के बारे में बताई गई एक दिलचस्प बात याद आती है। उस समय बाबा

भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े होने के बावजूद, उनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे, जो शायद एक सच्चे लोकतंत्र की वास्तकविक पहचान है। चुनाव परिणाम आने के बाद, मोदी जी राष्ट्रपति भवन में बाबा से मिलने आए। बातचीत के दौरान, बाबा ने मोदी जी से चुनाव के बारे में उनका विश्लेषण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि तीन दशकों के बाद किसी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। तब बाबा ने अपने विशिष्ट प्रोफ़ेसर वाले अंदाज़ में पूछा, 'और क्या?'' जब मोदी जी चुप रहे, तो बाबा ने बताया कि 2014 का लोकसभा चुनाव इतिहास में अनोखा था, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर एक नया चेहरा पहले ही घोषित कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी को मिला लोगों का अपार समर्थन केवल उनकी पार्टी के लिए नहीं था, बल्कि यह लोगों का श्री नरेन्द्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सीधा जनादेश था। दूसरे चुनावों के विपरीत, जहाँ प्रधानमंत्री का चेहरा जो तो मान लिया जाता है कि पहली बार सांसद बनने वाले व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार संसद भवन में प्रवेश किया। (पुरानी) संसद की सीढ़ियों पर 'प्रणाम' करने का उनका भावुक कदम हृदय को छू लेने वाला ऐसा क्षण था, जिसने करोड़ों भारतीयों के



जन-नेता नहीं रहे, उन्हें तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने चुना था। भारत के दो प्रधानमंत्री, श्री पी.वी. नरसिम्हा राव और श्री एच.डी. देवेंगौड़ा - तो प्रधानमंत्री बनने के समय संसद के सदस्य भी नहीं थे। सरल शब्दों में कहें तो, प्रधानमंत्री का चुनाव वरिष्ठ राजनेता करते थे। 2014 भारतीय राजनीति के चुनावी समीकरण में एक बहुत बड़ा बदलाव था, जहां देश की जनता ने श्री नरेन्द्र मोदी को लगभग 'राष्ट्रपति चुनाव' की ही तरह, स्पष्ट रूप से और बिना किसी संदेह के अपना प्रधानमंत्री चुना। उल्लेखनीय है कि 2014 से पहले श्री नरेन्द्र मोदी जी 'राष्ट्रीय' राजनीति में नथे। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने लंबे कार्यकाल के दौरान अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई थी, लेकिन 2014 उनका पहला लोकसभा चुनाव था। यह एक अनोखी बात है कि पहली बार सांसद बनने वाले व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार संसद भवन में प्रवेश किया। (पुरानी) संसद की सीढ़ियों पर 'प्रणाम' करने का उनका भावुक कदम हृदय को छू लेने वाला ऐसा क्षण था, जिसने करोड़ों भारतीयों के

हृदय में अपनी जगह बना ली। चुनाव में विजय का कभी भी कोई एक कारण नहीं होता; यह कई कारकों से जुड़ी एक जटिल प्रक्रिया है। भाजपा का जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन, अलग-अलग जातियों और समुदायों तक लगातार पहुंचने की रणनीति, अपनी गलतियों को शीघ्र पहचानना और तुरंत सुधार करने की इच्छाशक्ति — ये कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं जिन्होंने विद्यमान भाजपा को चुनाव जीतने वाली एक ऐसी शक्ति बना दिया है, जिसे वर्तमान में रोक पाना दुष्कार लगता है। हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि श्री नरेन्द्र मोदी जी का चेहरा शायद भाजपा का सबसे मजबूत ट्रंप कार्ड है। लोग उनमें एक ऐसा मजबूत नेता देखते हैं, जो अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर आगे बढ़ा है, न कि कांग्रेस की तरह वंशवादी विरासत या परिवार-शासित क्षेत्रीय पार्टियों की मजबूत पकड़ के कारण।

एक तरह से श्री नरेन्द्र मोदी भाजपा के पर्याय बन गए हैं। मैं हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बारे में बंगाल के मित्रों के साथ हुई कुछ बातचीत का उल्लेख करना चाहूँगी। जहां मेरे अपने रिश्तेदार

अभी भी कांग्रेस के कट्टर समर्थक हैं और बंगाल में कांग्रेस को मिले मामूली 2.9 प्रतिशत वोट शेयर में उनका भी योगदान था, वहीं मेरे अधिकतर दोस्तों और परिचितों ने भाजपा को वोट दिया था। चुनाव से पहले, मैं उनसे पूछती थी कि वे किस पार्टी को वोट देंगे। अधिकतर लोगों का उत्तर यही होता था कि वे 'मोदी' को वोट देंगे। मैं उन्हें याद दिलाती थी कि यह विधानसभा चुनाव है और मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनका उत्तर हमेशा यही होता था— 'ओई एक-ई व्यापार'—यानी 'बात एक ही है'।

श्री नरेन्द्र मोदी जी न केवल देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, बल्कि शायद स्वतंत्रता के बाद देश ने जितने भी प्रधानमंत्री देखे हैं, उनमें से वे सबसे मजबूत नेताओं में से एक हैं।

वे गठबंधन सरकारों, जो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं, के उन व्यावधानों (अक्सर ब्लैकमेल करने वाले तरीकों) का शिकार हुए बिना एक मजबूत और स्थिर सरकार देने में सफल रहे हैं। कोई उनकी कोई नीतियों या काम करने के तरीके से असहमत हो सकता है और लोकतंत्र में ऐसा होना बिल्कुल सामान्य बात है; लेकिन कोई भी उनके करिश्म में और 'आकर्षक भारत' के लिए प्रेरणा के तौर पर भारतीय मतदाताओं के साथ उनके जुड़ाव को नकार नहीं सकता। यह बात 2019 और फिर 2024 में भी स्पष्ट रूप से दिखी। आप श्री नरेन्द्र मोदी को पसंद करें या नापसंद, लेकिन आप 'ब्रांड मोदी' की अनेकवैधी नहीं कर सकते। बड़ा ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। एक आम नागरिक के रूप में, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वे लोगों से प्राप्त भारी जनादेश के साथ पूरा न्याय करें और हमारे देश को और भी ऊँचाइयों तक ले जाएँ।

(लेखिका एक स्तेम्भकार हैं और 'प्रणब माय फादर: अ डॉटर रिमेबर्स' पुस्तिक की लेखिका हैं। वह वर्तमान में 'प्रणब मुखर्जी लिगेसी फाउंडेशन' की संचालक हैं।)

एआई और इंटरनेट से बढ़ती डिजिटल थकान: कारण और समाधान

सुनील कुमार महला

आज का युग तकनीक का युग है और आज के इस तकनीक और डिजिटल युग में हर किसी में डिजिटल फ़टीग (डिजिटल थकान) तेजी से बढ़ती समस्या बनती जा रही है। दिनभर या यूं कहें कि लगातार स्क्रीन पर काम करना, बार-बार आने वाले नोटिफ़िकेशन, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, ऑनलाइन बैठकों और एआई आधारित टूल्स पर बढ़ती निर्भरता के कारण लोगों में मानसिक थकान, एकाग्रता की कमी, आँखों में तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए बनाए गए डिजिटल साधन कई बार मानसिक दबाव का कारण भी बन जाते हैं। इसलिए स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करना, नियमित अंतराल पर विराम लेना और डिजिटल संतुलन बनाए रखना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

कहना ग़लत नहीं होगा कि मोबाइल या लैपटॉप पर बार-बार आने वाले नोटिफ़िकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा तैयार की जा रही सामग्री, स्क्रीन पर लगातार काम करने की आदत और विभिन्न एआई टूल्स के बढ़ते उपयोग के कारण आज लोगों में मानसिक और डिजिटल थकान तेजी से बढ़ रही है। डिजेंबना यह है कि जिन तकनीकों और टूल्स को हमारी उत्पादकता बढ़ाने के लिए बनाया गया था, वे ही अब एकाग्रता में कमी, तनाव और 'बर्नआउट' का मुख्य कारण बन रहे हैं। ऑनलाइन लेक्चर, वर्चुअल मीटिंग्स, इंटरनेट पर उपलब्ध असंमित जानकारीयों, रील्स और शॉर्ट वीडियोयें न लोगों को इस कदर भाग लिया है कि फ़िकता बढ़ते समय भी ध्यान बार-बार मोबाइल फोन की ओर चला जाता है, जिसका सीधा असर हमारी स्मरण शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता पर भी पड़ रहा है। लगातार डिजिटल माध्यमों के संपर्क में रहने और एआई-आधारित टूल्स से मिलने वाले अलर्ट्स, रिमाइंडर्स व परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स के कारण आज मानसिक बोझ बढ़ रहा है।पाठक जानते हैं कि आज शिक्षा से लेकर कार्यस्थल तक एआई कौशल सीखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, लेकिन जब हम एआई के उत्तरो पर पूरी तरह निर्भर होने लगते हैं, तो

मादक पदार्थों का नशा - मस्तिष्क को अनियंत्रित करने वाला घातक जहर

डॉ. प्रितम भि. गेडाम



समस्त जीव-जगत में मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है और इसका प्रमुख कारण उसका विकसित मस्तिष्क है। मानव शरीर की प्रत्येक गतिविधि, निर्णय और व्यवहार का संचालन मस्तिष्क द्वारा ही किया जाता है। यदि मस्तिष्क सही ढंग से कार्य न

करे तो मनुष्य का अस्तित्व मात्र एक जिंदा लाश तक सीमित रह जाता है। दुर्भाग्यवश, नशा सबसे पहले और सबसे अधिक इसी मस्तिष्क पर आघात करता है। मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता को प्रभावित कर देता है, जिससे वह सही और गलत के बीच का अंतर समझने में असमर्थ हो जाता है। नशे की स्थिति में व्यक्ति का अपने व्यवहार और भावनाओं पर नियंत्रण कम हो जाता है। यही कारण है कि अनेक अपराधों के पीछे नशे की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। नशे की लत पूरी करने के लिए लोंग चोरी, लूट, हिंसा और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों का सहारा लेते हैं। आर्थिक तंगी बढ़ने पर कई बार स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि व्यक्ति अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ हिंसक व्यवहार करने लगता है। समाचारों में अक्सर ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं, जहाँ नशे की लत के कारण परिवार टूट जाते हैं और निर्दोष लोगों की जान तक चली जाती है।

नशा केवल मस्तिष्क को ही नहीं, बल्कि शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों को भी धीरे-धीरे नुकसान पहुँचाता है। इसका परिणाम अनेक गंभीर और महगी बीमारियों के रूप में सामने आता है, जो अंततः असमय मृत्यु का कारण बन सकती हैं। इसलिए नशा किसी भी रूप में मनोरंजन या राहत का साधन नहीं, बल्कि धीरे-धीरे जीवन को नष्ट करने वाला जहर है। भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय प्रत्येक वर्ष नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चलाता है। वर्ष 2026 में 17 जून से 26 जून तक 'नशा मुक्त सप्ताह' मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देशभर में विविध जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष की थीम है— "वैश्विक स्तर पर ड्रग समस्या: इससे उत्पन्न चुनौतियाँ और उनके नए समाधान।" यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नशीले पदार्थों की उपलब्धता और पहुँच पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गई है। छोटे बच्चों से लेकर युवाओं और बूढ़े तक, हर आयु वर्ग के लोग किसी न किसी रूप में इस समस्या की चपेट में आ रहे हैं। हाल ही में समाचारों में प्रकाशित जानकारी के अनुसार नागपुर में पांच महीनों के भीतर पांच करोड़ रुपये मूल्य की नशीली सामग्री जब्त की गई। यदि एक शहर की यह स्थिति है, तो पूरे राज्य और देश में मादक पदार्थों की

तस्करी का वास्तविक स्वरूप कितना व्यापक होगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। यह स्थिति केवल कानून-व्यवस्था की चुनौती नहीं है, बल्कि राष्ट्र के भविष्य के लिए भी गंभीर खतरा है। देश का युवा वर्ग किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। यदि यही युवा नशे की गिरफ्त में आ जाए तो समाज और देश दोनों का विकास प्रभावित होता है। पहले के समय में कुछ लोग यह मानते थे कि नशा थकान दूर करता है या मानसिक तनाव कम करता है। सीमित शिक्षा और मनोरंजन के साधनों के कारण ऐसी धारणाएँ प्रचलित थीं। किंतु आज, जब शिक्षा, तकनीक और जागरूकता के अनेक साधन उपलब्ध हैं, तब भी बड़ी संख्या में युवा नशे को आधुनिकता, मौज-मस्ती या सामाजिक प्रतिष्ठा से



जोड़कर देख रहे हैं। यह प्रवृत्ति अत्यंत चिंताजनक है।

जब परिवार का कोई एक सदस्य भी नशे का आदी हो जाता है, तो उसके दुष्परिणाम पूरे परिवार को भुगतने पड़ते हैं। परिवार आर्थिक संकट, मानसिक तनाव, सामाजिक अपमान और भावनात्मक पीड़ा का सामना करता है। नशे की लत व्यक्ति को धीरे-धीरे उसकी जिम्मेदारियों से दूर कर देती है। वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल होने लगता है और परिवार के अन्य सदस्य स्वयं को असुरक्षित तथा असहाय महसूस करते हैं। यदि परिवार का मुखिया ही नशे का शिकार हो जाए, तो पूरे परिवार का भविष्य संकट में पड़ता है। नशा केवल व्यक्तिगत या परिवारिक समस्या नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास में भी बड़ी बाधा है। इससे अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी और सामाजिक अस्थिरता जैसी अनेक समस्याएँ बढ़ती हैं। जिन देशों में नशीले पदार्थों का व्यापार बढ़ पैमाने पर फैला है, वहाँ सामाजिक और आर्थिक विकास गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। इसलिए नशे के विरुद्ध संघर्ष केवल स्वस्थता का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है।

बच्चों और किशोरों को नशे से दूर रखने में अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल बच्चों की इच्छाएँ पूरी करना या उन्हें भौतिक सुविधाएँ

उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। अभिभावकों को यह जानना चाहिए कि उनके बच्चे किन लोगों के संपर्क में हैं, कहाँ समय बिताते हैं और किन गतिविधियों में शामिल रहते हैं। बच्चों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को समझना और समय रहते उचित मार्गदर्शन देना आवश्यक है। परिवार में ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ बच्चे बिना किसी डर के अपने विचार और समस्याएँ साझा कर सकें। यदि माता-पिता बच्चों के मित्र बनकर संवाद स्थापित करें, तो बच्चों को गलत रास्तों पर जाने से रोकना जा सकता है। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उनके संस्कार, नैतिक शिक्षा और जीवन मूल्यों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

आज समाज में कई ऐसी घटनाएँ देखने को मिलती हैं, जहाँ नशे की हालत में लोग गंभीर अपराध कर बैठते हैं। ऐसी घटनाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि नशा व्यक्ति की निर्णय क्षमता को किस हद तक प्रभावित कर सकता है। इसलिए केवल अपराधों को दोगुी ठहराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन सामाजिक परिस्थितियों और लापरवाहियों पर भी विचार करना आवश्यक है, जो ऐसी घटनाओं को जन्म देती हैं। सरकारी आँकड़ों के अनुसार देश में नशे की शुरुआत की औसत आयु लगभग 12 से 13 वर्ष है, जो अत्यंत चिंताजनक तथ्य है। करोड़ों लोग शराब, गांजा, चरस, ओपिओइड्स तथा अन्य नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। विश्व स्तर पर भी नशीली दवाओं के उपयोग में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। अवैध मादक पदार्थों का उत्पादन और तस्करी संहतित अपराध को बढ़ावा दे रही है तथा अनेक देशों के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। इस समस्या से निपटने के लिए अत्यधिक कड़े कानून की आवश्यकता है। नशे की गिरफ्त में आए लोगों को उपचार, पुनर्वास और भावनात्मक सहयोग की भी आवश्यकता होती है। तनाव, अकेलापन, चिंता, सामाजिक दबाव और भावनात्मक अस्थिरता जैसे कारण भी युवाओं को नशे की ओर धकेलते हैं। इसलिए उन्हें सकारात्मक जीवन मूल्यों, स्वस्थ जीवनशैली, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती की दिशा में मार्गदर्शन देना आवश्यक है। देशभर में नशा मुक्ति केंद्र, पुनर्वास केंद्र और सहायता सेवाएँ उपलब्ध हैं। नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हेल्पलाइन नंबर 14446 भी संचालित किया है, जहाँ सहायता प्राप्त की जा सकती है। जीवन अमंगल है और इसे नशे जैसी विनाशकारी आदतों में बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। यदि हम स्वयं जागरूक बनें और दूसरों को भी जागरूक करें, तो नशामुक्त समाज और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। नशा जीवन में सुख, सफलता और सम्मान नहीं लाता, बल्कि धीरे-धीरे व्यक्ति, परिवार और समाज को विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि स्वयं नशे से दूर रहेंगे और दूसरों को भी इससे बचाने का प्रयास करेंगे। यही स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का सबसे मजबूत नींव है।

एक नजर**पीटी एवं पीव्हीपीटी प्रवेश परीक्षा 28 जून को**

रायगढ़, 25 जून। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा पीटी/पीव्हीपीटी प्रवेश परीक्षा का आयोजन 28 जून रविवार को किया जाएगा। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक आयोजित होगी। जिसके लिए दो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें शासकीय नटवर इंग्लिश स्कूल, रायगढ़ तथा किरोड़ीमल शासकीय पॉलिटेक्निक, चक्रधर नगर, रायगढ़ शामिल हैं।

कलेक्टर ने परीक्षा के सफल संचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर श्री धनराज मरकाम मोबा.97535-36151 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं शासकीय माध्यमिक विद्यालय सुराईपाली, तमनार के श्री विकास रंजन सिन्हा मोबा. 70009-29629 को सहायक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परीक्षा केंद्रों में निगरानी के लिए ऑब्जरवर् की भी नियुक्ति की गई है। जिसमें गवर्नमेंट नटवर इंग्लिश स्कूल, रायगढ़ के लिए श्री रविन्द्र दासे, सहायक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, रायगढ़ तथा किरोड़ीमल शासकीय पॉलिटेक्निक, चक्रधर नगर के लिए श्री कृष्ण कुमार प्रधान, प्रशिक्षण अधिकारी, आईटीआई तमनार को ऑब्जरवर् बनाया गया है।जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी ऑब्जरवर् 28 जून को सुबह 7 बजे तक जिला कोषालय, रायगढ़ में उपस्थित होकर गोपनीय परीक्षा सामग्री प्राप्त करेंगे। इसके बाद परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से ढाई घंटे पहले संबंधित परीक्षा केंद्रों तक गोपनीय सामग्री पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा समाप्त होने के बाद केन्द्राध्यक्ष से सीलबंद गोपनीय सामग्री प्राप्त कर उसे किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ में जमा कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी कारणवश नियुक्त अधिकारी परीक्षा दिवस पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो वे अपने अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को अधिकृत करते हुए वाहन की व्यवस्था करेंगे तथा इसकी सूचना तत्काल जिला कार्यालय को देंगे।

नैनो डीएपी एवं यूरिया प्लस के उपयोग से खेती की लागत में आई कमी : साव

महासमुंद्र 25 जून । आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर किसान अब कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह विकासखंड पिथौरा के ग्राम सलडीह के प्रतिशाली किसान श्री धनेश्वर साव जिन्होंने अपनी धान की फसल में नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया प्लस का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग कर बेहतर परिणाम हासिल किए हैं। श्री साव ने बताया कि उन्होंने बीज उपचार से लेकर पौध उपचार और फसल की वृद्धि अवस्था तक नैनो उर्वरकों का नियमानुसार प्रयोग किया। इसके परिणामस्वरूप धान की फसल अधिक ही-भरी, स्वस्थ एवं मजबूत विकसित हुई। फसल में रोग एवं कीटों का प्रकोप भी अपेक्षाकृत कम देखने को मिला, जिससे अतिरिक्त कीटनाशकों की आवश्यकता कम हुई और खेती की लागत में कमी आई। उन्होंने बताया कि नैनो उर्वरकों को अन्य उपयुक्त कीटनाशकों के साथ मिलाकर छिड़काव करने से समय और मजदूरी दोनों की बचत हुई। इससे कृषि कार्य अधिक सुविधाजनक और किफायती बन गया। फसल की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला, जिससे बेहतर उत्पादन की उम्मीद बढ़ी है।साव ने धान की बुवाई से पूर्व बीजों का नैनो डीएपी से उपचार किया। इसके लिए प्रति किलोग्राम बीज में 5 एमएल नैनो डीएपी का उपयोग किया गया। वहीं रोपाई से पहले पौधों की जड़ों को नैनो डीएपी घोल में उपचारित किया गया। फसल की 30 से 35 दिन की अवस्था में नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया प्लस का संयुक्त छिड़काव किया गया, जबकि दूसरा छिड़काव फूल आने से पहले पोखरी पानी अवस्था में नैनो यूरिया प्लस से किया गया। इन उपायों से फसल की आवश्यक पोषक तत्व समय पर प्राप्त हुए और पौधों की वृद्धि बेहतर हुई। प्रतिशाली किसान श्री धनेश्वर साव का अनुभव क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायक है।

एकलव्य विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 30 जून से

महासमुंद्र 25 जून । छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु काउंसलिंग की तिथियां और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोजित प्राक्कन परीक्षा की प्राविण्य सूची (मेरिट लिस्ट) और प्रतीक्षा सूची के आधार पर चयनित छात्रों के लिए यह काउंसलिंग 30 जून 2026 से शुरू होने जा रही है। काउंसलिंग का कार्यक्रम विकासखंड एवं जिला स्तर पर 30 जून, 1 जुलाई और 2 जुलाई 2026 को आयोजित होगा, राज्य स्तर पर 3 जुलाई 2026 तथा विशेष पिछड़ी जनजाति एवं विशेष आश्रित वर्ग के लिए 4 जुलाई 2026 को तथा आश्रित दिवस पर 6 जुलाई 2026 को उन अध्यार्थियों के लिए काउंसलिंग किया जाएगा ।

प्रेसवार्ता में कांग्रेस पर किया तीखा प्रहार, कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता आज भी जीवित

आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय : यज्ञदत्त शर्मा

तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

राजिम 25 जून। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ (राज्य मंत्री दर्जा) यज्ञदत्त शर्मा ने आपातकाल की बरसी पर राजिम में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन था। इसी तारीख को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए संविधान और लोकतंत्र दोनों को कुचल कर आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए देश पर आपातकाल थोप दिया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। इस अवसर पर प्रमुख रूप से राजिम विधायक रोहित साहू, भाजपा जिला महामंत्री चंद्रशेखर साहू, नगर पालिका अध्यक्ष महेश यादव, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राधेश्याम सोनवानी, राजिम मंडल अध्यक्ष रिकेश साहू मौजूद रहे।

आपातकाल की बरसी पर बुधवार को राजिम विश्रामगृह में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ (राज्य मंत्री दर्जा) यज्ञदत्त शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए



कहा कि आपातकाल एक राजनीतिक षड्यंत्र था, न कि कोई राष्ट्रीय संकट। इंदिरा गांधी ने सत्ता में बने रहने के लिए संविधान, लोकतंत्र और जन-अधिकारों को कुचल दिया था। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 की रात सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि लोकतंत्र की हत्या का प्रतीक बन चुकी है। प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया, समाचार पत्रों की बिजली काटी गई, सेंसरशिप थोप दी गई और हजारों निर्दोष नागरिकों, नेताओं और पत्रकारों को जेलों में ठूस दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी उसी आपातकालीन मानसिकता से प्रसन्न है। आज जब कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तब वह लोकतंत्र की दुहाई देती है, लेकिन जब सत्ता में होती है, तब विरोध की हर आवाज को दबाने का प्रयास करती है। कहा कि इस बात को खासकर याद रखना होगा कि आपातकाल के दौरान अभिव्यक्ति की आजादी को भी

कुचल दिया गया था, मीडिया पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। इमरजेंसी लगाने के तुरंत बाद अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई ताकि ज्यादातर अखबार अगले दिन आपातकाल का समाचार ना छाप सकें। आपातकाल के दौरान 3801 अखबारों को जब्त किया गया। 327 पत्रकारों को मौसोस कानून के तहत जेल में बंद कर दिया गया । 290 अखबारों में संपादकी विज्ञापन बंद कर दिए गए। रॉयटर्स सहित कई विदेशी न्यूज़ एजेंसियों के टेलीफोन और दूसरी सुविधाएं काट दी गईं। 51 विदेशी पत्रकारों की मान्यता खीन ली गई। 29 विदेशी पत्रकारों को भारत में एंट्री देने सेमना कर दिया गया ।उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जब देश में जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी कुलेश्वर साहू,ईश्वर साहू, बादल साहू, लालजी साहू,महेश देवांगन,जितेंद्र पेंदरिया उपस्थित थे।

हर गरीब को पक्का मकान दिलाने मैदान में उतरे विधायक रोहित

**तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता**

राजिम 25 जून । मोदी की आवास गारंटी को जमीन पर उतारने सक्रिय हुए विधायक रोहित साहू, 24 जून से गांव-गांव शुरू होगा आवास प्लस 2.0 सर्वे पक्के मकान के हक के लिए ग्राम सभाओं में पहुंचने की अपील। कहा कोई पात्र परिवार नहीं छूट्या गरीबों के आशियाने की लड़ाई में आगे आए रोहित साहू, आवास प्लस 2.0 सर्वे को लेकर जनता से की बड़ी अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के प्रत्येक आवासहीन परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 24 जून से आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण अभियान को लेकर राजिम विधायक रोहित साहू ने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि वे अपने-अपने ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में अनिवार्य रूप से शामिल हों और पात्र परिवारों का नाम सूची में दर्ज कराने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं।विधायक रोहित साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि देश का कोई भी गरीब परिवार बिना पक्के मकान के न रहे, और इसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री

विष्णु देव साय तथा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सर्वेक्षण के तहत सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWVL) का ग्राम सभाओं में वाचन, अवलोकन और परीक्षण किया जाएगा।विधायक साहू ने जानकारी दी कि शासन की मार्गदर्शिका और एसओपी के अनुसार

ग्राम सभाओं में प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी, साथ ही सूची में नाम जोड़ने, हटाने या त्रुटि सुधार के लिए दावा-आपत्ति भी प्राप्त की जाएगी। ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत इस स्थायी प्रतीक्षा सूची को आवास सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।उन्होंने क्षेत्र के सभी ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और पात्र हितग्राहियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने ग्राम पंचायत मुख्यालयों में पहुंचकर सूची का बारीकी से अवलोकन करें। यदि किसी पात्र परिवार का नाम सूची में छूट गया हो या किसी प्रकार की त्रुटि हो, तो वे दावा-आपत्ति की प्रक्रिया में शामिल होकर उसका निराकरण कराएं। विधायक रोहित साहू ने स्पष्ट कहा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी पात्र, गरीब और जरूरतमंद परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित न रहे।विधायक रोहित साहू ने इसे गरीबों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि राजिम विधानसभा क्षेत्र के हर जरूरतमंद परिवार तक योजना का लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह केवल सर्वेक्षण नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के सपनों को पकड़ी छत देने का अभियान है, जिसमें जनता की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है।

खरीफ सीजन में कृषि विभाग ने 18 दुकानों का निरीक्षण कर 37.45 क्विंटल बीज की बिक्री पर लगाई रोक

तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 25 जून। खरीफ सीजन के दौरान किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा जिलेभर में सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 23 जून को जिले के सभी विकासखंडों में 18 बीज विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बीज नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर विभिन्न बीज विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 37.45 क्विंटल बीज के विक्रय, वितरण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया।

उप संचालक कृषि श्री अनिल वर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खरसिया स्थित मेसर्स जय बालाजी एजेंसी, समलेश्वरी बीज भंडार पटेलपाली, बालाजी बीज भंडार पटेलपाली, मुकेश भींडर धरमजयगढ़, श्री श्याम कृषि केंद्र सिसरिया



तथा सागर कृषि केंद्र पुसौर में बीजों के स्रोत संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों द्वारा विक्रय किया जा रहे बीजों के वैध स्रोत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके चलते विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित बीजों की बिक्री पर रोक लगा दी गई।खरसिया स्थित जय बालाजी एजेंसी में अंकुर सीड एवं मनसा सीड के स्रोत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अंकुर सोनम एवं मनसा विरट धान बीज के स्टिक के विक्रय, वितरण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया। इसी प्रकार रायगढ़ विकासखंड

के समलेश्वरी बीज भंडार पटेलपाली, बालाजी बीज भंडार पटेलपाली, मुकेश भींडर धरमजयगढ़ एवं श्री श्याम कृषि केंद्र सिसरिया में पान सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के बीजों के स्रोत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर सार दिवस के लिए विक्रय प्रतिबंध लगाया गया। वहीं रायपुर स्थित सागर कृषि केंद्र में धान की किस्म आईआर-64 के स्रोत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उसके विक्रय पर रोक लगाई गई है। कृषि विभाग ने निरीक्षण के दौरान मासिक प्रतिवेदन एवं आवश्यक अभिलेखों का संधारण नहीं पाए

पीएम-अजय योजना के तहत स्वरोजगाार के लिए आवेदन आमंत्रित

रायगढ़, 25 जून । अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पीएम-अजय) योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें शासन की ओर से अनुदान की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, रायगढ़ द्वारा इच्छुक एवं पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि पीएम-अजय योजना के तहत विभिन्न खराय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इनमें किराना दुकान, मनिहारी, कपड़ा व्यवसाय, नाई सैलून, ब्यूटी पालर, टेलरिंग, फैसी स्टोर, मोटर मैकेनिक, साइकिल मरम्मत एवं दुकान, टीवी-रेडियो और मोबाइल रिपेरिंग, वार्डिंग, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोना-पत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य व्यवसाय शामिल हैं।

माध्यमिक विद्यालय पंचपारा में पाठ्यपुस्तक और ड्रेस का किया गया वितरण

**तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता**

रायगढ़, 25 जून। जनपद पंचायत पुसौर अंतर्गत ग्राम पंचायत पंचपारा स्थित माध्यमिक विद्यालय में नए शिक्षा सत्र के अवसर पर पाठ्यपुस्तक एवं स्कूल ड्रेस वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी श्री साहू के निर्देश एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी बी. पटेल के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में नव प्रवेशी विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक और स्कूल ड्रेस वितरित की गईं। कार्यक्रम में संकुल प्राचार्य श्रीमती हर, संकुल समन्वयक प्रयोग साव, संस्था प्रमुख श्री डी. नायक, कृषि सभापति मुक्तेश्वर पंडा, सरपंच श्रीमती योग्यता श्याम लाल पटेल, एसएमसी अध्यक्ष पूनी लाल पटेल सहित ग्रामीणजन एवं विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुक्तेश्वर पंडा ने विद्यार्थियों को सफलता के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि नियमित पढ़ाई, अनुशासन और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण से ही जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने बच्चों से समय पर विद्यालय आने, शिक्षकों द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने और कठिन विषयों का लगातार अभ्यास करने की अपील की।

समाचार संक्षेप

राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान 28 से 30 जून तक

रायगढ़, 25 जून। कलेक्टर के निर्देश पर जिले में बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान का आयोजन 28 से 30 जून तक किया जाएगा। तीन दिवसीय इस विशेष अभियान के तहत रायगढ़ जिले के शून्य से 5 वर्ष आयु वर्ग के 1 लाख 34 हजार 980 बच्चों को पोलियो वैक्सिन की दो बुंद पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सीएमएचओ डॉ. अनिल कुमार जात ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को निर्धारित तिथि पर नजदीकी पोलियो बूथ तक अवश्य लेकर आएँ और उन्हें पोलियो की खुराक दिलाकर इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. बी.पी. पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान का शुभारंभ रविवार 28 जून को जिले भर के 1307 पोलियो बूथों पर किया जाएगा। पहले दिन बूथ स्तर पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जबकि 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमों घर-घर जाकर उन बच्चों को पहला वकी जो किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे बच्चों को उनके घर पर ही पोलियो वैक्सिन पिलाकर प्रतिरक्षित किया जाएगा।

कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त, सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति और अवैध उत्खनन की व्यापक समीक्षा



रायगढ़, 25 जून। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मयंक चतुर्वेदी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था समीक्षा बैठक में जिले में कानून-व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति अभियान, अवैध उत्खनन, औद्योगिक सुरक्षा, आबकारी अधिनियम के प्रकरणों तथा विभिन्न संवेदनशील विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में विभागवार प्रगति का परीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़े सभी विषयों में विभागीय समन्वय, सतत निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, नशा एवं अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण, औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन तथा आमजन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में ज़ीरो टोलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते हुए जमीनी स्तर पर परिणाम सुनिश्चित करें तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी।कलेक्टर ने अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन पर प्रभावी अंकुश लगाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने राजस्व, खनिज, पुलिस एवं परिवहन विभाग को संयुक्त अभियान चलाकर नियमित जांच, सघन निगरानी एवं दैधियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

धमतरी बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल कार्बन कृषि जिला



धमतरी, 25 जून । कृषि को अधिक टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु-अनुकूल बनाने की दिशा में धमतरी जिले ने एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। जिला प्रशासन धमतरी एवं जलवायु प्रौद्योगिकी आधारित संस्था प्रिथु के मध्य आज एक महत्वपूर्ण समझौता साइन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के माध्यम से धमतरी को छत्तीसगढ़ के प्रथम मॉडल कार्बन कृषि जिला के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पहल के तहत जिले में दो चरणों में लगभग 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मुदा कार्बन संवर्धन (Soil Organic Carbon-SOC) परियोजना तथा 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ऑल्टरनेट वेंटिंग एंड ड्राइंग (AWD) आधारित धान उत्पादन परियोजना संचालित की जाएगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाना, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना, जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना है। प्रिथु के सह-संस्थापक श्री प्रबल तोमर ने बताया कि संस्था आगामी तीन वर्षों में लगभग 5 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस निवेश का उपयोग किसानों के क्षमता विकास, ग्रामीण युवाओं के कौशल उन्नयन, रोजगार सृजन, किसान आदान-प्रदान कार्यक्रमों तथा आधुनिक कृषि एवं जलवायु तकनीकों के प्रसार में किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के पश्चात उनके संपूर्ण जीवनचक्र में कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों को लगभग 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त होने की संभावना है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के साथ-साथ टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा और कृषि क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के प्रति अधिक सक्षम बनाया जा सकेगा।

मोदी की गारंटी और साय सरकार की संवेदनशील पहल से बदल रही भूमिहीन परिवारों की जिंदगी

तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 25 जून। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार समाज के कमजोर, वंचित और श्रमजीवी वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में संचालित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना जिले के हजारों भूमिहीन परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता जरूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन रही है।

रायगढ़ जिले में इस योजना के अंतर्गत 32 हजार से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। सहायता राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ-साथ परिवारों को समय पर आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। शासन की यह पहल उन परिवारों के लिए राहत लेकर आई है, जिनकी आजीविका मुख्य रूप से मजदूरी और पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भर है। जिले के नारीय क्षेत्र

भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार की मंशा समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने की है।

सहायता राशि से आसन हो रही पारिवारिक जिम्मेदारी

ग्राम कोसमनारा के हरि प्रसाद डनसेना ने बताया कि भूमिहीन होने के कारण परिवार की आजीविका मजदूरी पर निर्भर थी। सीमित आय में परिवार की जरूरतों और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना कठिन होता था, लेकिन योजना से मिलने वाली सहायता राशि ने आर्थिक बोझ कम किया है और भविष्य के प्रति

विश्वास बढ़ाया है। ग्राम कोसमनारा की कुत्ती देवांगन ने कहा कि योजना से प्राप्त राशि परिवार की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मददगार साबित हो रही है। वहीं कांशीचुआ के जगतमन सारथी ने बताया कि यह योजना भूमिहीन मजदूर परिवारों के लिए अत्यंत उपयोगी है, जिससे वर्तमान आवश्यकताओं के साथ भविष्य की जरूरतों की भी बेहतर योजना बनाई जा रही है। रेवती बाई ने कहा कि योजना ने उन्हें आर्थिक सुरक्षा का एहसास कराया है और परिवार के भविष्य के लेकर नया आत्मविश्वास दिया है।

सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना उनके लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का माध्यम बनकर आ रही है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना आज हजारों श्रमिक परिवारों के जीवन में खुशहाली लाते हुए प्रदेश में समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की दिशा को मजबूती प्रदान कर रही है।

एक नजर

आशीष गोयल सम्मानित



रायपुर, 25 जून। नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा आयोजित पीएम स्वनिधि महोत्सव एवं लोक कल्याण मेला में पीएम स्वनिधि योजना के सफा क्रियान्वयन एवं हितग्राहियों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में उल्लेखनीय योगदान के लिए केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के आशीष गोयल को महापौर मीनल चौबे द्वारा सम्मानित किया गया।

होनहार बच्चों को विप्र समाज देगा छात्रवृत्ति

रायपुर, 25 जून। विप्र सांस्कृतिक भवन प्रबंध समिति द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मेधावी और होनहार छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिन्हें आर्थिक समस्या के कारण अध्ययन में बाधा उत्पन्न हो रही है। अंतःसमाज के जरूरत मंद विद्यार्थी या उनके पालक विप्र भवन समता कालोनी रायपुर में आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ 10 जुलाई तक आवेदन जमा करें।

कार्यशाला में रिसर्च पेपर की उपयोगिता की दी गई जानकारी

रायपुर, 25 जून। छत्तीसगढ़ युवा विकास संगठन संचालित विप्र महाविद्यालय एवं शासकीय नदीन महाविद्यालय गुडियारी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिवस ऑनलाइन मोड के प्रथम तकनीकी सत्र में विषय विशेषज्ञ डॉ. प्रारुल दुबे (सिंबावोसिस इस्टीमेटेड आफ्टरकोलोनीज्म नागपुर) ने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन पर आधारित जानकारी प्रदान किया।

लोक कल्याण मेला का आयोजन

रायपुर, 25 जून। नगर पालिक निगम में महापौर नंदलाल देवांगन एवं आयुक्त युगल किशोर उर्वशा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोक कल्याण मेला का सफा आयोजन किया गया। मेले का उद्देश्य पथ विक्रेताओं एवं हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ प्रदान करना रहा।

लिधन

नरेन्द्र कुमार जैन

रायपुर, 25 जून। रायपुर प्रेस बिरादरी के सबसे वयोवृद्ध सदस्य नरेन्द्र कुमार जैन का बुधवार को निधन हो गया है। वे नोलेश जैन के पिता थे। उन्होंने 1957 से 2010 तक नवभारत प्रेस रायपुर के विज्ञापन विभाग में नियमित सेवाएं दीं।

योजना का लाभ विवाहित महिलाओं के लिए जल्द ही पोर्टल खोलने की तैयारी कर रहा है विभाग

महतारी वंदन योजना में फिर से जुड़ेंगे नाम : लक्ष्मी राजवाड़े कार्यकर्ताओं को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है भाजपा : साव

रायपुर, 25 जून। महतारी वंदन योजना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। योजना से अब तक नहीं जुड़ पाई विवाहित महिलाओं के लिए जल्द ही पोर्टल खोलने की तैयारी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि मुख्यमंत्री की अनुमति मिल चुकी है, और अगले एक सप्ताह के भीतर पोर्टल शुरू करने की तैयारी की जा रही है।



मंत्रि लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि पोर्टल खोलने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। सबसे पहले बस्तर संभाग के जिलों में पोर्टल खोला जाएगा, जिसके बाद प्रदेश के अन्य संभागों में भी आवेदन और पंजीयन की सुविधा शुरू की जाएगी।

योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, परिवार में उनकी भागीदारी को मजबूत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है। पोर्टल खोलने से बड़ी संख्या में ऐसी महिलाओं को राहत मिलेगी जो लंबे समय से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रही थीं।

पोर्टल शुरू होने के बाद पात्र महिलाएं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकेंगी। इसके लिए संबंधित विभाग की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे। महतारी वंदन योजना का दायरा बढ़ाकर अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को इसका लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है।

रायपुर, 25 जून। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को आधुनिक तकनीकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग में निपुण बनाने के लिए देशव्यापी अभियान चला रही है।



पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि भाजपा एक कार्यकर्ता-आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं की योग्यता और क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से ही लगातार विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

इसी कड़ी में प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों से विनियमित किए गए तीन-तीन प्रमुख कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से आमंत्रित कर प्रशिक्षित किया जा रहा है। यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, ये कार्यकर्ता जमीनी स्तर तक जाकर अन्य साधियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के सही और प्रभावी उपयोग का प्रशिक्षण देंगे।

बहुमंजिला भवनों, कोचिंग सेंटरों और होटलों का होगा ऑडिट

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा पर सख्त हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर, 25 जून। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बहुमंजिला आवासीय परिसरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कोचिंग संस्थानों, होटलों तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा और विशेष ऑडिट के निर्देश दिए हैं।



हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में हुई अग्नि दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसी घटनाओं से सबक लेकर सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

है। इसलिए सभी संबंधित संस्थानों में निश्चित सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान अग्निशमन यंत्रों एवं फायर सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता, वैध फायर एनओसी, अपातकालीन निकास मार्गों की व्यवस्था, भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, विद्युत वायरिंग एवं उपकरणों की स्थिति, सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था, प्राथमिक उपचार सुविधा, पेयजल एवं स्वच्छता व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी।

राजधानी के 4 कोचिंग संस्थानों में मिली गंभीर खामियां

नगर निगम ने सुधार के लिए 7 दिन का दिया अल्टीमेटम

रायपुर, 25 जून। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित एक इमारत में लगी भीषण आग में 15 लोगों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ में भी पहलियातन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है।

मानकों का परीक्षण किया गया। निरीक्षण में अनअकादमी, विद्यापीठ और एलन में अधिकता आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध पाई गईं। हालांकि, कुछ संस्थानों में वेंटिलेशन एवं क्षमता अनुरूप संचालन के संबंध में सुधारतात्मक सुझाव दिए गए हैं।

स्वागत



रायपुर, 25 जून। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल का आज यहां आगमन पर भव्य स्वागत किया गया।

बिजली बिल वृद्धि और अधोषिक्त बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन



रायपुर, 25 जून। रायपुर के डीडी नगर एवं खमतारई जेन में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ते बिजली बिल और अधोषिक्त विद्युत कटौती के विरोध में बिजली विभाग कार्यालयों में काले पोस्टर चسपा कर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।

छग के तीन खिलाड़ियों ने बढ़ाया राज्य का मान

रायपुर, 25 जून। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के तीन खिलाड़ियों ने बीसीसीआई के इमर्जिंग मेन्स टूर्नामेंट 2026 में जगह बनाकर प्रदेश का मान बढ़ाया है।

छग मोटरयान नियम को व्यावहारिक व युक्तियुक्त बनाने की मांग

रायपुर, 25 जून। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी के नेतृत्व में चेम्बर प्रतिनिधिमंडल एवं छत्तीसगढ़ ऑटोमोबाइल रिसिलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रदेश के परिवहन मंत्री केदार कश्यप जी से सौजन्य मुलाकात की।



विशेष आग्रह किया। श्री थौरानी ने आगे कहा कि पुरानी गाड़ियों के ओनरशिप ट्रांसफर पर लागू 1: के नए टेक्स से बाजार में भारी मंदी है। उन्होंने इस टेक्स को तुरंत वापस लेकर पूर्ण की भांति केवल मामूली शुल्क ही लेने की बात कही। साथ ही डीलरों से मांगी जा रही भारी-भरकम बैंक गारंटी को पूरी तरह निरस्त करने की मांग की गई।

साय सरकार ने ढाई साल में कांग्रेस की 20 योजनाओं को बंद किया: दीपक बैज

रायपुर, 25 जून। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार ने ढाई सालों में या तो कांग्रेस सरकार के समय चलाई जा रही योजनाओं का नाम बदला है या फिर उन योजनाओं को दुर्भवापूर्वक बंद किया है।



प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार ने ढाई साल में छत्तीसगढ़ की जनता को निराश किया है। साय सरकार पिछली सरकार की इन 20 महत्वपूर्ण योजनाओं को बंद किया।

पुराने विधानसभा भवन में शुरु होगी फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई

रायपुर, 25 जून। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित पुराना विधानसभा परिसर अब जल्द ही फैशन और टेक्सटाइल शिक्षा का नया केंद्र बनने जा रहा है।

तक नवा रायपुर में संस्थान का अत्याधुनिक और स्थायी परिसर बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक छात्रों की पढ़ाई और प्रशासनिक कार्य इसी पुराने विधानसभा भवन से संचालित किए जाएंगे।

युवाओं को मिलेगी टेक्सटाइल और परिधान क्षेत्र में वैश्विक शिक्षा। नए विधानसभा भवन के नवा रायपुर में स्थानांतरित होने के बाद, इस ऐतिहासिक पुराने भवन के रचनात्मक उपयोग को लेकर राज्य सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है।

नवा रायपुर में बनेगा स्थायी परिसर: उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में हड़बड़ा की स्थापना को लेकर 17 अप्रैल 2025 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में औपचारिक मंजूरी दी गई थी।

रायपुर, 25 जून। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित पुराना विधानसभा परिसर अब जल्द ही फैशन और टेक्सटाइल शिक्षा का नया केंद्र बनने जा रहा है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए पुराने विधानसभा भवन को अस्थायी कैंपस के रूप में आवंटित किया है।